



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड : 50

शिमला, शनिवार, 24 अगस्त, 2002/2 भाद्रपद, 1924

संख्या : 21

विषय सूची		
भाग-1	वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	870—892
भाग-2	वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	—
भाग-3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेंशियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	893—898
भाग-4	स्थानीय स्वायत्त शासन, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग-5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन ..	898—914
भाग-6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन ..	—
भाग-7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं ..	—
—	अनुपूरक ..	—

24 अगस्त, 2002/2 भाद्रपद, 1924 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्ति में 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या एफ० आई० एन०-2-सी(ए) एस० एस०/4-3/96-560—65, दिनांक 1 अगस्त, 2002.	वित्त विभाग (निदेशालय लघु बचत)	हिमाचल प्रदेश लघु बचत निदेशालय, लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 का इसके अंग्रेजी रूपान्तरण सहित प्रकाशन।
संख्या एस० एफ० ई०-ए०(बी०) 2- 1/94 (लूज), दिनांक 25 जुलाई, 2002.	वन विभाग	हिमाचल प्रदेश वन विभाग, रजिस्ट्रार वर्ग-1 (राजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2002 का इसके अंग्रेजी रूपान्तरण सहित प्रकाशन।

भाग-1 — वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि**हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट****NOTIFICATIONS***Shimla, the 3rd/7th August, 2002*

No. HHC/GAZ/14-58-75-X-16141.—It is hereby notified for information of the members of Himachal Pradesh Judicial Service that 41st Departmental Examination under Rule 4 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 1973 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001, on the following dates :—

Date	Paper/Subject	Time
Thursday, December 26, 2002	Criminal Law	10.00 A. M. to 1.00 P. M.
	Civil Law	2.00 P. M. to 5.00 P. M.
Friday December 27, 2002	Revenue Law-I	10.00 A. M. to 1.00 P. M.
	Revenue Law-II	2.00 P. M. to 5.00 P. M.
Saturday, December 28, 2002	Accounts	10.00 A. M. to 1.00 P. M.
	Constitutional Law	2.00 P. M. to 5.00 P. M.

By order,

SURJIT SINGH,
Registrar General/Secretary,
Departmental Examination Committee.

Shimla, the 5th August, 2002

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XII-15881.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H. P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Sub Judge-cum-JMIC(2), Palampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the court of Sub Judge-cum-Additional Chief Judicial Magistrate (1), Palampur and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of Class-III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014—Administration of Justice" during the leave period of Shri Rattan Singh, Sub Judge-cum-ACJM(1), Palampur w. e. f. 1-8-2002 to 15-8-2002, or until he returns from leave.

Shimla, the 9th August, 2002

No. HHC/GAZ/14-134/82-II-16443.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to order the cancellation of un-availed 10 days earned leave sanctioned with effect from 5-8-2002 to 14-1-2002 with permission to prefix Sunday falling on 4-3-2002 and to suffix gazetted holiday falling on 15-8-2002, in favour of Shri Ravinder Prakash, Senior Sub Judge-cum-CJM, Mandi, sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-134/82-II-15334-43, dated 27-7-2002.

Shimla, the 9th August, 2002

No. HHC/GAZ/14-196/89-I-16452.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 15 days paternity leave w. e. f. 12-8-2002 to 26-8-2002 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 9th and 10th August, 2002 in favour of Shri K. K. Sharma, Additional CJM-cum-SJIC, Jogindernagar.

Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of Additional CJM-cum-SJIC, Jogindernagar, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त विभाग
(कोष तथा लेखा संगठन)

अधिसूचना

शिमला-9, 1 अगस्त, 2002

संख्या फिन (टी0 प्रार0) बी0 (2) (7)-40/89—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री नानक चन्द वर्मा, संयुक्त नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) जो कि इस समय हिमाचल प्रदेश, कोष तथा लेखा संगठन के कार्यालय में कार्यरत हैं राजकीय सेवाओं से वाधक्य आयु पूर्ण करने के पश्चात्, दिनांक 31-12-2002 (बाद दोपहर) सेवा निवृत्त होंगे।

एस0 के0 सूद,
प्रधान सचिव।

मिचार्ड एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002

संख्या सिचार्ड 11-77/2002-कांगड़ा.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर मार्बजनिज प्रयोजन हेतु नामतः शां व काठगड़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में नलकूप नं0 38 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिशेख में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐय सभी व्यक्तियों का, जो इसमें सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और भूमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित प्रथम अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिशेख में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना कनेहपुर के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिना : कांगड़ा	तहसील : इन्दौरा
गांव	क्षेत्र
1	2
काठगड़	हैक्टेयरों में
	0 04 50
	0 03 28
जिसा	2
	0 07 78

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002

संख्या सिचाई 11-72/2002-कुल्लू

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002.

संख्या सिचाई 11-58/2002-कांगड़ा.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सकड़यालू, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में सम्पत्ति सड़क सीवरेज ज्वालामुखी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अभिकर्तों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित प्रथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए महर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समारहता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा	तहसील : देहरा
गांव	खसरा नं०
1	2
सकड़यालू	869/663/1
	664/1
किता . . 2	0 03 01

यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः* भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अभिकर्तों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित प्रथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए महर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समारहता, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव शाड़ावाई परगाणू फाटी व कोठी बजौरा, तहसील बजौरा, कुल्लू में रास्ता सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भूतल के निर्माण हेतु।

जिला : कुल्लू	विस्तृत विवरणी	तहसील : कुल्लू
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र
1	2	बीघा बिस्वा
शाड़ावाई परगाणू फाटी	1039/1/1	0 03 04
व कोठी बजौरा	1559/1040/1	0 01 12
	1560/1040/1	0 01 00
	1039/3/1/1	0 03 04
	1043/1	0 00 04
किता . . 5		0 09 04

*गांव दियार, तहसील व जिला कुल्लू में जल भण्डार टैंक पेयजन योजना दियार के निर्माण हेतु।

संख्या सिचाई 11-70/2002-कुल्लू

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002.

दियार	टुकड़ा नं० 1/1	0 14 19
*गांव डोला फाटी बजौरा, तहसील व जिला कुल्लू में मटोरेज टैंक पेयजन योजना हाट बजौरा के निर्माण हेतु।		

संख्या सिचाई 11-73/2002-कुल्लू।

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002.

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र
डोला फाटी बजौरा	1096/1	बीघा बिस्वा
		0 5

शिमला-2, 2 अगस्त, 2002

संख्या सिचाई 11-52/2001-शिमला.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सांगडी, तहसील व जिला शिमला में सीवरेज स्कीम शिमला टाऊन के निर्माण हेतु भूमि की जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समारहता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश देने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समारहता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने में पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समारहता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी			
जिला : शिमला		तहसील : शिमला	
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बिस्वा	
1	2	3	4
सांगटी	42/1/1	0	2
	2/1	1	9
	29/1	0	4
	30/1	0	1
	110/34/1	0	1
	110/34/2	0	10
	32/1	0	5
किता	7	2	12

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002

संख्या सिचाई 11-69/2002-सिरमौर.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बिरला, उप-तहसील ददाह, जिला सिरमौर में पम्प हाऊस बिरला के निर्माण हेतु भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सोलन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : सिरमौर		तहसील : ददाह	
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बिस्वा	
बिरला	161/1	0	8

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002

संख्या सिचाई 11-57/2002 सोलन.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गुलाहडी, तहसील कसौली, जिला सोलन में पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सोलन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : सोलन		तहसील : कसौली	
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बिस्वा	
गुलाहडी	68/2	12	7

यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः* भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव घण्डावल, तहसील व जिला ऊना में उठाऊ सिचाई योजना घण्डावल के निर्माण हेतु।

संख्या सिचाई 11-63/2002-ऊना।

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002.

विस्तृत विवरणी

जिला : ऊना		तहसील : ऊना	
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	
1	2	3	
घण्डावल	691/1	0 00	98
	693/1	0 02	64
	694/1	0 00	72
किता	3	0 04	34

*गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना में जल भण्डार के निर्माण हेतु।

संख्या सिचाई 11-59/2002-ऊना।

शिमला-2, 5 अगस्त, 2002.

पंजावर	1013/1	0 01	96
--------	--------	------	----

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव।

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th July, 2002

No. Shram (A)7-1/2002.—In exercise of the powers vested in him under Section 17(I) of the Industrial Dispute Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards in the H.P. Rajpatra announced by the Presiding Officer, Labour Court of the following cases;—

S. No.	Ref. No. and Particulars	Section	Remarks.
1	2	3	4
1.	Ref. No. 106/1997—Shri Romesh Chand Vs. HPSEB Nahan & Ors.	10	Publication
2.	Ref. No. 103/1996—Harnam Singh Vs. HPSEB Patiala & Ors.	10	-do-
3.	Ref. No. 3/1998—Sh. Krishnu Ram Vs. Electrical Divisional Ghumarwin, Distt. Bilaspur.	10	-do-
4.	Ref. No. 111/1998—Sh. Roop Singh Vs. G. M. Rosin & Turpentine Factory Nahan & Ors.	10	-do-
5.	Ref. No. 15/1998—Sh. Nanku Vs. Distt. Statistical Officer, Bilaspur (H.P.).	10	-do-
6.	Ref. No. 2/1998—Sh. Kishori Lal Vs. M/s Kangra Steels Teh. Nalagarh, District Solan.	10	-do-
7.	Ref. No. 183/1998—Sh. Gribu Ram Vs. D. M. H. P. State Forest Corpn P/Sahib.	10	-do-
8.	Ref. No. 87/1999—Sh. Kuldeep Chand Vs. M/s Dharam Pal & Satyapal.	10	-do-
9.	Ref. No. 56/1998—Bhupinder Singh Vs. Hitkari Parties Ltd. Parwanoo, Solan.	10	-do-
10.	Ref. No. 260/1998—Sh. Ramesh Chand Vs. HPSEB, Rajgarh & Others.	10	-do-
11.	Ref. No. 8/1998—Sh. Kuldeep Singh Vs. C.F.J.V.	10	-do-

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Labour Court, Shimla

Ref. No. 106 of 1997

Instituted on : 1-4-1997

Decided on : 31-3-2002

1. Shri Romesh Chands/o Balbir Singh.
2. Shri Tapinder Singh s/o Sh. Diwan Singh.
3. Shri Dhanveer Singh s/o Sh. Kesho Ram.
4. Shri Bholar s/o Shri Kundia Ram.
5. Shri Atma Ram s/o Shri Devi Ram.
6. Shri Sada Nand s/o Shri Chuhi Ram.
7. Shri Naresh Kumar s/o Shri Inder Singh.
8. Shri Bhagat Ram s/o Shri Budia Ram

9. Shri Munia Rams/o Shri Tadia Ram.
10. Shri Rakesh Mohan s/o Shri Pritam Singh
11. Shri Dharam Singh s/o Shri Sunder Singh.
12. Shri Gopal Singh s/o Sh. Hari Singh

.. Petitioners.

Versus

The Executive Engineer, HPSEB (Electrical) Division, Nahan, (H.P.) .. Respondent.

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioners : Shri A. K. Gupta, Advocate.

For respondent : Shri S. P. Sharma, AR.

AWARD :

The following reference has been received from the appropriate government :—

“Whether the termination of services of Shri Ramesh Chand and 11 other workers (list enclosed) by the Executive Engineer, Himachal Pradesh, State Electricity Board, Nahan Division, Nahan, District Sirmour (HP) without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of Section 25(F) of the Industrial Disputes Act, 1947 on completion of 240 days’ continuous service is legal and justified, if not, to what relief of service benefits including back wages, seniority and amount of compensation, the above aggrieved workmen are entitled ?”

2. The reference has been received from the appropriate Government with regard to the illegal termination of 12 workmen employed by the State Electricity Board, Nahan. In the joint claim petition filed by the petitioners through Shri A. K. Gupta, Advocate, it is mentioned that all the petitioners have completed more than 240 days of service and their services were terminated without complying with the provisions of Industrial Disputes Act. Hence they are entitled to be re-instated with all the benefits. Further that as per the certified Standing Orders, petitioners were entitled to a notice of 10 days even if they have not completed 240 days of service and hence their termination is illegal and unjustified. It is also submitted that principle of first come last go was not followed.

3. In the reply filed by the respondent, preliminary objection has been taken that the jurisdiction lies with the Administrative Tribunal and not with this forum. Secondly that their is no legal vested rights of the petitioner to claim the relief. Thirdly that petition is hit by the voice of delays and laches.

4. On merits, it is contended that the services of the petitioners were never terminated rather they left the job on their own. Further that petitioners were very casual in their work and they have worked only as per Annexures— R-1 to R-9, which shoes that they have never completed 240 days of work in any calendar year. It is submitted that there is no violation of Section 25-F of the Act. Hence, claim petition deserves to be dismissed and the reference may be answered against the petitioners.

5. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 12-8-1998:—

1. Whether the termination of the petitioners are illegal and have not complied the provisions of Section 25-F of the I.D. Act, 1947 and also Standing Orders Act ? If so, its effect ? OPP.
2. Whether the claim petition of the petitioners is barred by delay and laches ? If so, its effect ? OPR.
3. Relief.

FINDINGS :

6. *Issue No. 1.*—In order to prove their contention, petitioner Shri Ramesh Chand has appeared in the witness

box and has mentioned that his claim is similar to that of other petitioners and that they have worked with the respondent as per Ex. P-1, which is the proforma prepared by the Conciliation Officer during the conciliation proceedings. He has also tendered attendance cards Ex. P-2 to P-11. He further contended that the record of the respondent got burnt in fire. He also contended that none of the petitioners left the job on their own. Further that new persons were retained. However, in the cross-examination he has admitted that he does not know the exact number of petitioners and that he cannot say about the presence or absence of other workers. He also admitted that no written representation was made by him. This is the entire evidence led by the petitioners. Petitioner have also filed affidavits.

7. In rebuttal of this evidence, respondent has examined three witnesses. One is Shri S. P. Dheer, who has produced the work chart of petitioner Ex. R-1 to Ex. R-9. He has also mentioned that they did not complete 240 days and they left the job themselves. He admitted that he was not the SDO at the relevant time and that no notice had been given to the petitioners regarding their absence from duty.

8. Shri B. B. Bansal, Assistant Executive Engineer has stated that Shri Rajesh Kumar was working in his division and he is still working with them and has become regular work-charged. He has also tendered Ex. R-10, which is the application of Shri Rajesh Kumar mentioning therein that he does not press his claim in the Court.

9. Shri V. C. Goel who is Additional Superintending Engineer filed a counter affidavit to the affidavits filed by the petitioners. He has mentioned that petitioners No. 1 to 9 in the claim petition were working with them, whereas the remaining 3 have never worked as per the record. He has been given suggestion that the record of the deptt. got gutted in fire which suggestion is admitted, but the witness has maintained that the record was re-made on the basis of cash book. He has also admitted that no notice of 10 days was also given to the petitioners. In the affidavits filed by the petitioners it is mentioned that they have completed 240 days of service with a definite mention of dates of joining and termination. However, there is no supporting document in favour of these submissions made in the affidavits. These affidavits have been countered by the department by filing counter affidavits of Sh. V. C. Goel, who has stepped in the witness box to face cross-examination. As per these affidavits and also as per man days chart, which have been appended with individual affidavit. It is clear that 3 of the petitioners i.e. petitioners No. 10, 11 and 12 mentioned in the claim petition have not been engaged by the respondent. Therefore, in view of the counter affidavit and the record produced by the respondent I am of the view that petitioners No. 10, 11, 12 are not entitled to any relief claimed.

10. As regards other petitioners they have also not completed 240 days of work in the calendar years. However even if 240 days were not completed, petitioners have referred to the certified standing orders which have been made applicable in 1984 as per which ten days notice was required to be given. Admittedly no notice was served on the petitioners under these certified standing orders. A specific allegations has been made in the claim in this regard, but no reply has been given to these averments. Respondent has neither mentioned that certified standing orders are not applicable nor has disputed that a ten days notice was required to be given before terminating their services. So these allegations have been impliedly admitted by the respondent. The reference which has been received in this Court also speaks of any notice, charge sheet or enquiry in addition to the non-compliance of the provisions of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. Therefore, the fact remains that the notices which were required to be given under the certified standing orders have not been served by the respondent on the petitioners and their termination except petitioner No. 9 Munia Ram who has only worked for 30 days in 1986 is violative of the Certified Standing Orders.

11. So 8 petitioners namely Sarv Sh. Ramesh Chand Tapinder Singh, Dhanvir Singh, Bholar, Atma Ram, Sada Nand, Naresh Kumar and Bhagat Ram are entitled to be reinstated as their termination is violative of certified standing orders. Respondent has not proved that petitioners have abandoned the job. Hence their termination amounts to retrenchment.

12. Now coming to the consequential benefits the petitioners have come to the court at a very belated stage. Therefore, they are not entitled to the relief of back wages and continuity of service from the date of termination. They are only entitled to the relief of reinstatement from the date of the receipt of the reference in this court. They are also not entitled to the back wages for the similar reason. Hence issue is decided accordingly.

RELIEF

13. Keeping in view the aforesaid discussion I hold that the petitioner No. 1 to 8 namely Ramesh Chand, Tapinder Singh, Dhanvir Singh, Bholar, Atma Ram, Sada Nand, Naresh Kumar and Bhagat Ram are entitled to be reinstated in service with continuity and seniority from the date of the receipt of the reference in this Court, but without back wages. As regards petitioners No. 9 to 12 namely Munia Ram, Rakesh Mohan, Dharam Singh and Gopal Singh are concerned, they have not proved their employment with the respondent and are not entitled to any relief. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate government for its publication in the H.P. Rajpatra.

Announced in the Open Court today this 31st Day of March, 2002.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H.P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 103 of 1996

Instituted on : 21-9-1996

Remanded on : 13-11-2000

Decided on : 18-4-2002

Shri Harnam Singh & 20 others c/o Pradhan Lok
Nirman Mazdoor, Ekta Union, Jogindernagar
.. Petitioners.

Versus

1. Chairman, P.S.E.B., The Mall Patiala.
 2. Secretary PSEB, The Mall, Patiala.
 3. S. E. Shanan Power House PSEB, Jogindernagar.
- .. Respondents.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioners : Shri N. L. Kaundal, AR.

For respondent : Shri V. K. Gupta, AR.

AWARD :

The following reference has been received from the appropriate government:-

"Whether the termination of services of Shri Harnam Singh and 20 other workers (list enclosed) by the Superintending Engineer, Punjab State Electricity Board, Shanan Power House, Jogindernagar

District Mandi (H.P.) without any notice. charge-sheet, enquiry and compliance of Section 25(F) of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified if not, to what relief of past service benefits and amount of compensation, the aggrieved workmen are entitled to ?”

2. All the 21 petitioners have filed separate claim petitions raising similar issues. It is contended that petitioners were working in Shanan Power House, Jogindernagar, District Mandi and the respondent indulged in unfair labour practice and terminated their services wrongfully and illegally due to their Trade Union activities. It is also contended that no casual leave, earned leave, medical leave was given to them and termination of the service was done without any notice or retrenchment compensation. Petitioners have mentioned their dates of appointment and termination in their individual claim petitions.

3. In the reply filed by the respondent separately to individual claim petitions, two preliminary objections have been taken that reference is bad in law as it is a time barred claim and has been preferred after a gap of all most 18 years. Secondly that the reference is regarding the termination of the workers, whereas the petitioners have submitted their case for re-employment under Section 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947 (In short the ‘Act’), which is beyond the scope of the reference. Hence cannot be adjudicated upon.

4. On merits, it is denied that petitioners ever worked under Respondent No. 2. It is asserted that there is no relationship of master and servant between the parties. Further that Mechanical Construction Division of the Board at Shanan Power House was a separate unit and was abolished by the Punjab State Electricity Board during the period 1982 to 1984 and since the particular division is not in existence, re-employment cannot be given to the petitioners. Respondent has also mentioned that petitioners never worked under the respondents. Hence, the claim petition does not survive.

5. On the pleadings of the parties, following issues were framed on 29-3-1997 :—

1. Whether the termination of services of the petitioners is in violation of Section 25-F of the I.D. Act on the grounds as alleged ? OPP.
2. Whether the reference is bad in law as alleged ? OPR.
3. Whether this Court has no jurisdiction to entertain, try and adjudicate upon this reference in hand ? OPR.
4. Relief.

5. Some evidence on behalf of the petitioner had been led and case was listed for respondents evidence when the respondents challenged the validity of the reference before the Hon’ble High Court of Himachal Pradesh and Hon’ble High Court *vide* its order dated 18-9-1997 in CWP No. 227 of 1997 held that the reference made by the Government of Himachal Pradesh on 10-9-1996 to the Labour Court is illegal and against the settled principles of law and accordingly quashed the reference order. This order of the Hon’ble High Court was challenged before Hon’ble Supreme Court which set-aside the order of 10-9-1996 and observed that :—

“The High Court though notices that the proceedings arises under Section 10 of the Industrial Disputes Acts and making of a reference thereto is administrative in character still it has examined this matter as if sitting in appeal on the reference made. Infact the scope of the investigation in such a matter is very limited and in this case the two issues could not have been decided except by adjudication before the concerned competent authority.

It is also directed that the concerned Labour Court/Industrial Tribunal to adjudicate the reference as ordered by the Government and that while doing so, it shall examine the two questions referred to by the Hon’ble the Supreme Court.”

6. The file thereafter was received in this Court and petitioners moved application for additional evidence, which was allowed. The respondents also moved application for amendment of written statement which was also allowed and three additional issues were framed on the amended written statement. Thereafter remaining evidence was examined and arguments were heard :

- 3A. Whether the order of reference is bad as it has not reflected the real dispute. If so, its effect ?
...OPR.
- 3B. Whether a joint reference on 21 workmen is bad in law as alleged ? If so, its effect ?
...OPR.
- 3C. Whether the reference is in contravention of provisions of Industrial Disputes Act, and Article 166 of Constitution of India ?
...OPR.

4. Relief.

FINDINGS :

7. Issue No. 1, 2, 3 & 3A.—I will take up Issue No. 1, 2, 3 and 3A collectively as these issues go to the root of the case. The contention of the respondent is that reference is bad in law as it is belated, and secondly that it does not reflect the real controversy between the parties. It is submitted that all the petitioners were allegedly terminated between the period of 1979 to 1983, whereas the reference has been made by the government in the year, 1996 i.e. after a delay of all most 13 years. Therefore, the dispute having become stale and non existent should not have been referred for adjudication. It is submitted that Hon’ble High Court has appreciated the law in this respect and had held that reference after such a long period could not have been made by the State Government. It is further submitted that though the orders passed by Hon’ble High Court were set aside by Hon’ble Supreme Court, on the point of jurisdiction by observing that Hon’ble High Court is not sitting as a Court of appeal and so the effect of delay and laches can be decided by the Labour Court/Industrial Tribunal, but the issue is open and has to be decided. It is argued that delay in filing the reference has made the dispute stale and non existent and cannot be entertained by the court at this late stage.

8. The contention of the petitioners on the other hand is that limitation act is not applicable to the Industrial Disputes Act and therefore, the delay cannot defeat the rights of the petitioners. It is also contended that in view of the judgement of Hon’ble Supreme Court, the objection regarding delay stands repelled and cannot be re-agitated.

9. I have considered the arguments of both the parties. No finding on merit has been given on this issue by Hon’ble the Apex Court. The order passed by Hon’ble High Court has been set-aside holding that it did not have the jurisdiction to adjudicate this point and these questions can be adjudicated by Labour Court/Industrial Tribunal in the course of adjudication of the reference. Therefore, Hon’ble Supreme Court has not ruled that delay in this case does not defeated the right of the petitioners. Rather the question is still open and has to be adjudicated by this forum.

10. On this point both the parties have relied upon various judgments. Reliance has been placed by the petitioners on 2001-LLR 900 (SPAN KUMAR PANDIT Vs. U.P. STATE ELECTRICITY BOARD), learned counsel for the petitioner has submitted that Hon’ble Supreme Court has held that the word “at any time”

used in the Section are *prima facie* indicator of a period without boundary. The facts of the petition, which was pending before Hon'ble Apex Court are however, different. In that case, the petitioner and few other workers had been retrenched and those other workers who were members of a union had raised the dispute after the retrenchment. The petitioner who filed the petition later had mentioned in his petition that he was given to understand that as and when the case of the other petitioner will be decided, he will be given the benefit accordingly, he did not agitate the matter earlier. However since the benefit was not extended to him, so he had to come to the Court. So in the circumstances, it was held by Hon'ble Supreme Court that the petitioner had not woken up to the dispute after a long gap, rather that there were circumstances due to which he did not approach the Court earlier. However, in this case, there are no such circumstances which may show that the petitioners were vigilant about their rights and did not raise the demand for some valid reason. Rather it has come in the statements of the petitioners that they simply did not raise this issue till 1996. They neither made any representation nor approached any authority with regard to their retrenchment. Therefore, the judgment relied upon by the petitioner is of no help to them.

12. On the other hand, there are authorities of our own Hon'ble High Court as well as of Hon'ble Apex Court where the staleness of the claim has been held to be a valid reason for disallowing the claim. In CWP No. 398 of 2001, Hon'ble High Court of H. P. has held in its decision of 12th September, 2001 that though there is no limitation prescribed for referring the dispute to an Industrial Tribunal, yet it is only reasonable that dispute should be referred as soon as possible after the Conciliation proceedings have failed. No doubt this authority is with regard to the jurisdiction of the Hon'ble High Court to adjudicate upon the reference, which has been made belatedly, yet in principle it is held in the case:

"that a stale dispute causes the fading of the dispute and if it is not kept alive by the workman, then no industrial dispute could be said to have existed or apprehended. In 2001 (2) RSJ-5, Hon'ble Supreme Court has held that whether any relief to the workman should be denied on the ground of delay or it should be appropriately moulded is the discretion of the Tribunal depending on the facts and circumstances of the case and the discretion is to be exercised judicially."

(emphasis supplied)

Similarly in 2001 LLR 157, Hon'ble Supreme Court has held:

"Whether relief can be declined on the ground of delay and laches, depends on the facts and circumstances of each case. In this case, claim was made almost after a period of 13 years without any reasonable or justifying ground and there was nothing on record to explain this delay as held by the Tribunal. When the respondent did not make claim for 13 years without any justification and on merits also he had no case, the Tribunal did not rightly grant him any relief."

13. Therefore, the law is fairly settled that if there is unexplained delay of about 12 to 13 years, then it amounts to the fading away of the dispute and if the dispute has not been kept alive by the petitioner workmen, then it amounts to the dispute becoming non-existent.

14. The facts of the present case show that between the period of 1983 to 1996, the petitioner did not make any representation or demand. The demand was raised for the first time in 1996. Till then the petitioners kept on sleeping over their rights. They did not make any representation to the respondent or to the Labour Department and did not keep the dispute alive. They suddenly woke up to their rights in the year, 1996 for

the first time. There is no reason mentioned by them as to why they did not raise the dispute for 13 long years. There is absolutely no Explanation for such a long delay. I, therefore, have no hesitation to hold that the claim of the petitioners has become stale and non-existent and no relief can be granted to them.

15. The reference has also been challenged on the ground that the stand of the respondent before the Conciliation Officer was that the petitioners were never their employees and there was no relationship of employer and workmen between them. However, the reference which has been sent by the H. P. Government is worded in such a manner so as to assume that there existed a relationship of workmen and employer and the only question for adjudication is whether termination was legal and justified. Again, I will refer to the decision of Hon'ble Supreme Court in the case FIRESTONE TYRE & RUBBER CO. OF INDIA (P) LTD. V. THEIR WORKMEN reported in the FACTORIES JOURNAL REPORTS VOLUME 59, where the jurisdiction of Labour Court/Industrial Tribunal is confined only to adjudicate upon the point referred and incidental thereto. I have gone through the failure report filed by the Conciliation Officer, which is exhibited as RW-1/A. In this report, it has been specifically mentioned by the Conciliation Officer that "it has been pleaded that petitioners were not the employees of Shan Power House, Jogindernagar." Therefore, the real controversy raised was whether petitioners were in fact the workmen employed under the respondents and whether there was a relationship of Employer and workman between them.

16. So not withstanding the wording of the reference regarding the legality of the termination of the petitioners, the question whether there exists relationship of employer and workmen can be decided as it is incidental to the point referred for adjudication. Question of validity of termination will only arise if the relationship of master and workmen is established.

17. In this regard except statements of some of the petitioners on oath and Ex. PW-5/B, there is no evidence to prove this fact. Shri Ranknu Ram, Kundan Lal, Furan Chand, Harnam Singh and Shiv Lal though have appeared in the witness box, but have neither produced any appointment or termination order to show that they were appointed in the Construction Works Division, which is still existing. They also did not seek the record of the relevant period from the respondent to prove their claim. Though respondents on their own have taken up the stand that no record pertaining to the employment of the petitioners is available with them, but petitioners on their part are neither in possession of any such record of employment themselves, nor they tried to summon such record from the respondent to prove their case. Their statements also are not sufficient to prove that they were the employees of the Shan Power House in any particular division some 13 to 15 years back or that they completed the mandatory period of 240 days during such employment and were entitled to the notices and retrenchment compensation under section 25-F of the Act.

18. Now coming to the certificate Ex. PW-5/B which has been issued in favour of one of the petitioner Shri Shiv Lal by SDO, Shan Power Civil Construction Sub-Division, Jogindernagar certifying that Shri Shiv Lal s/o Shri Kanshi Ram had worked as work charge M. Mate w.e.f. 28-11-77 to 16-7-1983 under that Sub-Division. This certificate does not prove the actual working days nor the person issuing this certificate has been examined to establish the authenticity of this document. On the other hand, the respondent has examined Shri B. D. Sethi to show that as per the instructions issued by the Board which is Ex. RW-3/A, experience certificate can be issued only by the Controlling Authority who was the XEN of the division. It is submitted by the respondent that if such a certificate has at all been issued, then the same has been issued by an un-authorised person and therefore, cannot be relied upon. In my opinion, certificate Ex. PW-5/B is a vague document and has not

been issued by an authorised person. Moreover, it does not support the claim of all the petitioners who were working for the respondents because certificate RW-5/B had been issued by an Assistant Engineer in favour of one of the petitioners only.

19. The respondents have also submitted that since no record is available, therefore, it cannot be said as to on what terms and conditions and under which division petitioners were given employment, if at all, they were the employees of the Shanan Power House. It is also submitted that the work of construction of 50 MW project had been completed and the petitioners if at all were employed under this project, were phased out as per law on the completion of work. So unless until, it is proved that the petitioners were the employees of respondent, and the provisions of Industrial Disputes Act was though applicable but were violated for the purpose of last come first go or in terms of non compliance of provisions of Section 25-F of the Act, it cannot be assumed that termination of the petitioners was invalid or illegal.

20. I agree with this submission of the learned counsel for the respondent. In the examination-in-chief of Shiv Lal, it has come that he was appointed in a work relating to 50 MW extension project. He has been given suggestion in the cross-examination that he was only employed for the construction work of 50 MW project and that persons were being retrenched as and when the work finished. It shows that if the petitioners or any of them were employed for the construction of 50 MW project and that work had come to a close, their services could be terminated legally on the completion of the work and so they had no claim to remain in service after the work had finished, unless & until they could show that such termination was not in accordance with Industrial Disputes Act. However, again at the risk of repetition, I hold that there is no proof that petitioners were the employees of respondent and had been terminated without compliance of Industrial Disputes Act. No other petitioner has brought any proof that he was working in a division, where work is still going on, but still he was retrenched. So, the claim of the petitioners is not proved. I, therefore, hold that the petitioners have failed to prove these issues as neither it is proved that petitioners were the employees of the respondent or were terminated without complying with the provisions of Section 25-F of the Act. They have also failed to prove that the dispute survives after a period of 13 years. Therefore, these issues are decided against the petitioners and in favour of the respondent.

21. *Issue No. 3B.*—It is submitted by the respondents that though 21 demands notice were issued by 21 workmen individually, but all the notices have been clubbed under one reference, which is bad in law. Though it is not disputed that separate demand notices were served and a single reference has been made to the Court. Yet since the same dispute was raised in all the notices and respondent was the same institution/department, therefore, no prejudice has been caused to the petitioner or the respondent by clubbing these notices. All the demands have been dealt with collectively by the Conciliation Officer who has submitted one failure report in which the dispute raised by all the petitioners have been found to be identical. Therefore, there is no multifariousness of the cause of action which could defeat the case. Therefore, I hold that the joint reference of 21 workers is not against the law and decide the issue against the respondent.

22. *Issue No. 3 C.*—Against it has been submitted that the reference is bad as it has not been made by the State Government, but by the Labour Commissioner. However, the Labour Commissioner has acted as per the powers delegated to him by the State Government, which is very apparent from the wording of the reference itself. He has acted in the name of State of Himachal Pradesh and delegation of powers has been provided for under Section 59 of the Industrial Disputes Act. It is mentioned that in case of appropriate government being State

Government, the powers can be exercised by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification. Therefore, the Labour Commissioner being a delegated authority is authorised to act on behalf of the State Government, so reference does not suffer from any such flaw. I, therefore, hold that the reference is valid and legal and decide this issue against the respondent.

RELIEF :

23. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, the reference is decided against the petitioners and let a copy of this award be sent to appropriate government for its publication.

Announced in the Open Court today this 18th Day of April, 2002.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR)

Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Mrs Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H.P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 3 of 1998.

Instituted on : 12-7-1998

Decided on : 4-5-2002

Shri Krishnu Ram s/o Sh. Mangat Ram, VPO
Nivili, Bhater, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.)
.. Petitioner.

Versus

Executive Engineer, Electrical Division. Ghumarwin,
District Bilaspur, (H.P.)
.. Respondent.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioner : Shri Sunder Singh, AR.

For respondent : Shri S. P. Sharma, AR.

AWARD :

Following reference has been received from the appropriate government:—

“कि क्या श्री कृष्ण राम सुपुत्र श्री मंगत राम को अधिशाषी अधिनियन्ता, विद्युत मण्डल, घुमारवीं जिला बिलासपुर द्वारा दिनांक 5-11-1988 को नौकरी से निकालना न्याय संगत है यदि नहीं तो कामगार किस पद, सेवा लाभ, बरिष्ठता का पात्र है ?”

2. Petitioner alleges that he was working as Blacksmith on daily wages from 26-11-1981 and worked as such till 5-11-1988, when his services were terminated illegally. It is contended that the seniority was not properly fixed and he was terminated ignoring the principle of first come last go. Further that he was not paid the retrenchment compensation in terms of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 (In short as the 'Act'). So the termination from service is bad in law and he is liable to be re-instated with all consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondent, preliminary objections have been taken that there is no enforceable cause of action, that no rights of the petitioner has been infringed and that petition is belated.

4. On merits, it is submitted that petitioner was working as Blacksmith on daily wages from 9-11-1981 till 26-12-1983 and then he left the job on his own. However, he was again re-engaged on 27-4-1986 on his own request and worked till 25-10-1988 when his services were terminated for want of work and funds. It is

submitted that he was served with one month's notice and retrenchment compensation was also paid to him. The working days chart has been annexed by the respondent. It is submitted that retrenchment compensation for the period from 9-11-1981 to 26-12-1983 cannot be given to the petitioner as he had left the job himself and was not terminated. Therefore, the reference is liable to be decided against the petitioner.

5. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed to following issues on 12-11-95:—

1. Whether the termination of the services of the petitioner is bad in law and in view of Section 25-F of the I.D. Act? If so, its effect. OPP.
2. Whether the petition is barred by delay and laches? OPR.
3. Relief.

FINDINGS

6. *Issue No. 1.*—Petitioner while appearing in the witness box in support of his own claim has mentioned that he worked continuously from 26-12-1981 to 5-11-1988 and that he was paid the dues compensation. Further that retrenchment compensation of Rs. 490/- was paid to him only on 11-12-1990. He has also mentioned that persons junior to him have been shown in the list. EX. P-1. Petitioner has also exhibited the notice EX. P-2 and the representation made by him is EX. P-3. In his cross-examination he has mentioned that he was working in Kandaur Sub-Division from 27-12-83 to 26-4-86 and that Hari Ram and Mast Ram were working with him. He has also mentioned that he was given pay for this period against the vouchers. He has also mentioned that though some money was given to him, but he was not aware that it was in lieu of the retrenchment compensation. He also mentioned that now he is working as black-smith in his own house.

7. In rebuttal Shri B. L. Thakur, Assistant Engineer has deposed on behalf of the respondent and was mentioned that petitioner left the job on 26-4-1983 and then was again re-employed on 27-4-1986. Further that notice was given to him when he was terminated on 5-11-1988 that he was also paid the retrenchment compensation, he has also mentioned that initially retrenchment compensation was sent to him by money order vide EX. R-3, but was refused. But thereafter, it was paid as per EX. R-4 on 11-12-1990. He has also mentioned that no one junior to him was retained and the seniority list is EX. R-5. His cross-examination is to the effect that no notice was given to the petitioner when he left on 5-11-88 such is denied. It is mentioned that petitioner was offered retrenchment compensation when he was terminated, but he refused. He has denied the suggestion that 20 new recruitments have been made during this period. He has also denied that petitioner remained in continuous service from 1981 to 1986. He has been given suggestion that retrenchment compensation was paid to him after two years which he was denied.

8. I have heard the learned counsels the parties and gone through the record. The mandays chart which has been produced by the respondent and which is EX. RA/1 shows that petitioner has worked from 9-11-1981 to December, 1983 and thereafter he has worked from December 1986 to 25-10-88. Though petitioner is alleging that he did work in Kandaur Sub-Division between 1983 to 1986, but there is no documentary evidence in support of this claim of the petitioner. Petitioner has ascertained that he was paid wages against vouchers for this period and if it was so, he could have summoned the record from the concerned Sub-Division for the relevant period. Therefore, I do not accept the plea of the petitioner that he was working continuously from 1981 to 1988.

9. Next question which arise is whether the termination of the petitioner is 1988 is in accordance with

the Act or not. No doubt a notice has been served upon the petitioner which has been duly exhibited and is EX. R-2 whereby one month's notice has been given to the petitioner, but this letter does not offer any retrenchment compensation to him. This letter is silent about any retrenchment compensation and though retrenchment compensation seems to have been paid to the petitioner in 1990, but this cannot be considered to be in accordance with law as respondent was required to offer and pay the retrenchment compensation simultaneously alongwith the termination order. There is nothing record to show that any oral offer was made to the petitioner to receive the retrenchment compensation, when he refused. No doubt, one Money order EX. R-3 was sent to the petitioner, which he allegedly refused, but this document has not been properly proved. The document mentions that a sum of Rs. 18450/- has been sent to 83 persons as per same list but that list and acknowledgement of this MO is not proved. So, it is not established that any MO was sent to the petitioner on his termination. Rather the retrenchment compensation has been paid to him after 2 years of his termination, which is not in accordance with law and his termination cannot be held to be legal in these circumstances.

10. Next question which comes for consideration is that for what period petitioner was entitled for retrenchment compensation. Admittedly, petitioner had worked from 1981 to 1983 as per EX. RA/1 and though it is contended by the respondent that petitioner left the job on his own, but no such supporting documents have been placed on record. It is admitted by RW that no notice was given to the petitioner when he left the job on 27-4-1983. There is nothing on record to show that petitioner was re-engaged on his own request in 1986. So it seems that petitioner was disengaged on 27-4-1983 after having put in more than 240 days continuous work. Therefore, for the purpose of calculating the retrenchment compensation. The period of employment from 1981 to 1983 should have also been taken into consideration. Therefore, I hold that neither the retrenchment compensation was calculated properly nor it was paid alongwith the termination order. Therefore, the termination of the petitioner is bad in law and is liable to be re-instated. The petitioner has mentioned that he is working as Black-smith in his own house. In these circumstances, though petitioner is entitled to the seniority and continuity from the date of reference, but he is not entitled to any back wages. Issue is decided accordingly.

11. *Issue No. 2.*—No arguments have been addressed on this issue. Otherwise also, petitioner was allegedly terminated in 1988 and he did represent to the department and sent a representation in 1992 which was replied to by the department meaning thereby that he was alive to his right. Hence, this issue is decided against the respondent.

RELIEF

12. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that neither the retrenchment compensation was calculated properly nor it was paid alongwith the termination order. Hence, the termination is bad. I, therefore, order his re-instatement from the date of the reference in this Court with seniority and continuity, but without back wages. Reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriated government for its publication.

Announced in the Open Court today this 4th day of May, 2002.

Seal.

Sd/-

(ARUNA KAPOOR),

Presiding Judge,

H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor Presiding Judge.
(H.P.) Labour Court, Shimla

Ref. No. 111 of 1998

Instituted on 18-8-1998

Decided on 9-5-2002

1. Shri Roop Singh s/o Shri Munesh Ram.
2. Shri Rajender Kumar s/o Shri Shree Ram.
3. Shri Abid Ali s/o Shri Babib-ullah.
4. Shri Chaman Lal s/o Shri Rulia Ram.
5. Shri Kanhaya Lal s/o Shri Mata Prasad.

Petitioners.

Versus

1. The General Manager, Rosin & Turpentine Factory, Nahan, District Sirmaur.
2. The Managing Director, H.P. State Forest Corporation Ltd., Shimla, H. P.

Respondents.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioners : Shri A. K. Gupta, Advocate.

For respondents : Shri R. K. Khidta, Advocate.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate government :—

"क्या श्री रूप सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, राम सोणी नन्द, डाकघर नोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर व अन्य कामचारों द्वारा बतौर दैनिक वेतनिक बेलदार 240 दिन से अधिक की सेवाएं करने उपरान्त नियोजक (1) प्रबन्धक विदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम हिमाचल प्रदेश (1) महाप्रबन्धक, बिरोजा व तारपीन फैक्टरी (वन निगम) नाहन जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा श्रमिक की सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना 29-9-1997 तिथि से समाप्त करना उचित एवं न्याय संगत है? यदि नहीं तो उक्त श्रमिक किन सेवा लाभों व अतिपूर्ण के पात्र है?"

2. Petitioner have alleged that they were employed as daily waged labourers in the factory of the respondent from July, 1991 except Petitioner No. 1 who joined in July, 1995, but their services were terminated in utter disregard of the Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. It is contended that some juniors were retained whereas petitioners were terminated and so they are entitled to re-instatement with back wages and other consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondent, a preliminary objection has been raised that Petitioner No. 1 has filed an affidavit and withdrawn from the reference and therefore, his claim does not survive and other petitioners were not sponsored by the Employment Exchange. Therefore, this reference petition deserves to be rejected.

4. On merits, it is submitted that petitioner remained as daily wagers till 27-9-1997 against conditional employment and they were allowed to work for short period as per permission granted by the General Manager of the factory. It is submitted that petitioners were engaged on daily wages w. e. f. 28-8-1995 and not from July, 1995.

5. It is submitted that Respondent No. 2 had given the permission to engage 7 daily wagers after following the codal formalities and the names from Employment Exchange were called and since the names of the petitioners were not received from the Employment Exchange, so they were not kept. Hence, in these circumstances, petition deserves to be dismissed.

6. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 7-8-99:—

1. Whether the termination of the petitioners are illegal and void in view of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947? If so, its effect?

OPP.

2. Relief

FINDINGS

7. Issue No. 1.—The claim regarding petitioners No. 1 is stated to have been compromised and a copy of the affidavit has been exhibited as Ex. R-1. Therefore, the claim of Petitioner No. 1 stands withdrawn. As regards the claim of other petitioners, it has not been disputed that they have completed 240 days of employment with the respondent before their services were terminated. Two of the petitioners Rajender Kumar and Abid Ali have made the statement on oath to this effect and no cross-examination has been done that they have not completed 240 days. However, it is suggested to them that they were employed on contract basis and that the contract expired in 1997. This shows that petitioners admittedly joined the respondent in August, 1995 and worked with them till 1997 and during these two years, they remained on work for more than 240 days in each year. It is also not disputed by the respondent that the job was not left by the petitioners themselves. Rather they were not given extension and person who were sponsored by the Employment Exchange were kept in their place. So the only question which survives for consideration is whether the employment of the petitioners was contractual for a specific period and come to an end on completion of the contract period. In this regard, statement of Shri Ajai Kumar, the Factory Manager is that petitioners were given conditional employment for a specific period and he has relied upon a letter Ex. R-2, which has been sent by the Head Office. Ex. R-2 is a letter written by the Managing Director to the General Manager authorising him to engage 8 mazdoors for a period of less than 3 months. However, the question remains whether such a condition was imposed on the petitioners while offering them employment and whether an employment for a period of less than 3 months is justified. Though some letters Ex. R-3 to Ex. R-5 written by Rajinder Kumar, Roop Singh and Abid Ali have been produced by the respondent in which they have offered to work for a period of less than 3 months and not to claim any benefits at the time of retrenchment, but these documents have not been put to the petitioners when they came in the witness box. So it can not be said that these documents were voluntarily executed and were signed by them voluntarily. There is also nothing on record show that the appointment letters given to the petitioners had this specific condition that they will be employed for only a specific period. Moreover, except these Ex. R-3 to Ex. R-5, there is nothing on record to show that after the completion of the period of three months on what condition petitioners were offered re-employment. Even their appointment initially was conditional yet they continued in the employment of the respondent for all most three years. In the absence of any further orders or record, it cannot be said that petitioners were employed for a specific period thereafter also. In these circumstances, once they completed 240 days of employment in a calendar year, their services could not have been terminated without complying with the procedure prescribed under Section 25-F of the Act. I find support from 2001 LLR-312, which is a judgment delivered by Hon'ble the Supreme Court.

8. The next question which arises is whether an offer employment of short period for less than three months despite the work being available for longer period can be held justified. It is established that names were sought from the Employment Exchange and 7 daily waged workers employed. The letter to this fact is Ex. R-6 which shows that the work was available for 7 daily wagers.

However, instead of continuing with the petitioners, requisition was sent to the Employment Exchange for sponsoring the names. Therefore, despite there being availability of work, offering of job only for less than 3 months is not justified as has been held in 1988-Lab. I. C-1094-H. P. High Court.

9. Even if the services of the petitioners were to be dispensed with because regular hands were to be employed through Employment Exchange, yet petitioners were entitled to the notice and retrenchment compensation, which has not been paid to them. So for all these reasons, their termination cannot be held valid and they are entitled to be re-instated in job with seniority and continuity in service. However, since it has not come in the evidence that petitioners were not gainfully employed during this period, therefore, I do not think it proper to allow full back wages to the petitioners and allow the wages @ 20% of their last wages drawn. Issue is decided accordingly.

RELIEF

10. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the termination of the petitioner is illegal and they are entitled to be re-instated in job with full back seniority and continuity of service with 20% back wages of the last wages drawn. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate government for its publication.

Announced in the open Court today this 9th day of May, 2002.

Seal. Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour,
Court, Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Labour Court, Shimla.

Ref. No. 15 of 1988

Instituted on 26-2-1998

Decided on 9-5-2002

Shri Nanku s/o Shri Malhi, H. No. 36, Gurudwara
Road, Bilaspur. .. Petitioner.

Versus

District Statistical Officer, Bilaspur, H. P.
.. Respondent.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes
Act, 1947.

For petitioner : Shri Sunder Singh, AR.

For respondent : Shri H. K. Sharma, Advocate.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate government:—

"Whether the termination of services of Shri Nanku s/o Shri Melhi, Gurudawara Road, Bilaspur H. P. by the Statistical Officer, Bilaspur, H. P. on 5-4-1997 on the pretext that his work and conduct was not satisfactory is legal and justified? If not, what amount of back wages, past service benefits and relief, the above worker is entitled to from the above Employer?"

2. The claim petitioner Shri Nanku has alleged that he was employed as Part time Sweeper on 1-1-1980 and remained in the employment till 4-4-1997 when his services were terminated arbitrarily without serving any

notice on him and without issuing any chargesheet etc. It is submitted that new Part-time sweeper has been appointed. Further that he had completed more than 240 days of continuous service in each year. Yet, compliance of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 (In short as the 'Act') has not been made. He has contended that violation of Section 25-G and H of the act has also been done. So, his termination is illegal, unjustified and liable to be set-aside and he is liable to be re-instated in job with all consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondent, preliminary objection has been taken that this Court has no jurisdiction as the District Statistical Officer is not covered under the Industrial Disputes Act. Further on merits, it is submitted that petitioner was working from 26-3-1985 and he was rightly terminated on 4-4-1997 as he misbehaved and left the office threatening that he will register a case in the court of law against the respondent. It is also submitted that petitioner was a part time worker, but he was forcing the respondent to regularise him which could not be done.

4. It is also mentioned that petitioner has acceded the age of 60 years as his date of birth is 6-11-1928. Lastly, it is mentioned that the benefits of temporary, regular employees are not admissible to the part time employees. Further that since petitioner was negligent in his duties and was guilty of indiscipline, so his termination cannot be termed as retrenchment and no retrenchment compensation can be paid to the petitioner in view of the facts and circumstances of the case.

5. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 15-12-1998:—

1. Whether the termination of the petitioner is bad in view of Section 25-F of the Industrial disputes Act? If so, its effect? **OPP.**
2. Whether this Court has no jurisdiction if so, its effect? **OPR.**
3. Relief.

FINDINGS

6. Issue No. 1.—The termination order of the petitioner (Ex.PX) reads that on 4-4-1997, petitioner came to the office of the District Statistical Officer and started demanding employment for the full day and when he was told that it is not possible, then he started abusing the District Statistical Officer and left the Office by threatening that he will file a case against him. Further that earlier also, he had sent a false complaint to the Deputy Commissioner which was enquired into by the Police. Lastly, it reads that in these circumstances, it has become impossible to take work from petitioner Nanku and so his appointment as Part-time worker stands terminated w. e. f. 5-4-1997.

7. There is no specific denial that petitioner has not completed 240 days of continuous service in a completed calendar year. The specific assertion of the petitioner is that he has worked for more than 240 days in each calendar year has not been specifically disputed and the only dispute is that he was not employed in 1980 rather that he was employed in the year, 1985. Hence the petitioner was to be governed under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, in the matter of termination of his service or if he was found guilty of any misconduct like abusing the superior, disobeying the order, creating newsense or not reporting for work etc, then it was required that he was to be chargesheeted and a legal enquiry was held against him, where opportunity is given to the petitioner to put up his defence. However, the letter Ex. PX shows that petitioner misbehaved with the District Statistical Officer and in view

of his misbehaviour and threatening, his services were terminated with immediate effect. The very language of the letter shows that he was terminated by way of punishment, though, he could not have been terminated without first enquiring into the misconduct. So in view of the letter Ex.PX itself, there is a clear violation of the provisions of the Industrial Disputes Act. Hon'ble Supreme Court has held in 2001 LLR 312 and also in 2000-LLR-577 that without complying with the provision of Section 25-F of the Act, any termination or retrenchment of a workman who has put in more than 240 days of service is bad and cannot be held justified. Therefore, without even considering the other material on record and only on the basis of Ex. PX, it can be held that retrenchment of the petitioner for the misconduct alleged in the letter Ex. PX cannot be held to be justified.

8. A plea has been raised in Para-7 of the reply that petitioner stood superannuated on completion of 60 years of age. It is also mentioned that his date of birth according to the record is 6-11-1928. Firstly this is not a point to be decided under the reference because the reference is specific as to whether the termination of the petitioner on the pretext that his work and conduct was not satisfactory is legal and justified. Therefore, in the present reference, the point of date of superannuation of the petitioner cannot be decided. Moreover, as per averment of the respondent, petitioner completed the age of 60 years on 6-11-1988. Still, he was allowed to work in the office till 1997. The respondent Shri Vijay Ram while appearing in the witness box has mentioned that since petitioner is not covered under the Industrial Disputes Act and there were no other instructions, therefore, he was allowed to continue to work after completion of 60 years of age. This explanation is totally devoid of merits. Even if it is assumed that Industrial Disputes Act is not applicable to the facts of the present case (this point I will be deciding under issue No. 2) thus his case was to be governed by the service rules applicable to the employees of the State of H. P., which also provides for the superannuation at the age of 60 years for Class-IV employees. So by merely saying that there were no instructions and the petitioner was allowed to work even after the age of 60 years is a lame excuse and is a defence which has been taken up for covering the termination of the petitioner.

9. Respondent has examined a witness from Welfare Department who has produced the record as per which the petitioner has taken old age pension from 1-7-1989. I would also like to refer to the statement of Shri Vajay Ram, where he has mentioned that it was not possible to keep the petitioner for a full day, so he was making complaints to the Deputy Commissioner which were also enquired into. He has also introduced a fact that the younger brother of the petitioner stood superannuated in 1998. He has also mentioned that though an affidavit was given by the petitioner regarding change of his date of birth, but that affidavit was not accepted by the Department. However, in view of the discussion above, this part of the evidence is irrelevant for the purpose of deciding the reference.

10. So, in the facts and circumstances of the case, it is suffice to say that the termination of the petitioner for the alleged misconduct without affording him any opportunity of being heard by way of enquiry or charge-sheet cannot be held justified under the Industrial Disputes Act and so his termination on that account is illegal and void. The issue is decided accordingly.

11. *Issue No. 2.*—An objection has been raised that this Court has no jurisdiction in the matter. Since the petitioner is a daily waged employee and is a workman, therefore, the Industrial Disputes Act is applicable to the petitioner. The definition of industry is very vast under the Act, and it includes any business, trade, undertaking manufacture or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workman. Therefore this definition is *vide* enough to cover the present dispute.

12. No arguments were addressed on this point by the respondent nor any evidence has come that the respondent is not covered under the Act. So, I hold at this forum has the jurisdiction in the matter and decide the issue accordingly against the respondent.

RELIEF

13. In view of the findings given on issues above, I hold that the termination of the petitioner on 5-4-1997 on the pretext that his work and conduct was not satisfactory is illegal and unjustified. However, in view of the admission of the petitioner that he stood superannuated on 13-12-2001 (which is suggestion given to RW-2), petitioner now cannot be ordered to be re-instated in service. He is entitled to the payment of back wages and other consequential benefits, till in date of his retirement subject to the adjudication on the point of date of superannuation/retrenchment by an appropriate forum. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate Government.

Announced in the Open Court today this 9th day of May, 2002.

Seal. S/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Labour Court, Shimla.

Ref. No. 2 of 1998.

Instituted on : 12-1-1998.

Decided on : 13-5-2002.

Shri Kishori Lal Sharma Village, Chiriwala, P. O.
Bhatia, Tehsil Nalagarh, District Solan, (H. P.)
.. Petitioner.

Versus

M/s Kangra Steels Pvt. Ltd., V. Kripalpur, P. O. &
Tehsil Nalagarh, District Solan, (H. P.) .. Respondent.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioner : Shri Hem Raj . AR.

For respondent : Ex-Parte.

AWARD

Following reference has been received from the appropriate Government:—

"क्या प्रबन्धक पक्ष में 0 कांगड़ा स्टील लि0, गांव कुपालपुर, तहसील नालागढ़ द्वारा कामगार श्री किशोरी लाल फ़िटर को बिना किसी कारण व बराबरी के नौकरी से निकालना व्यापकित व तर्कसंगत है? यदि नहीं तो कामगार श्री किशोरी लाल किस लाभों का पात्र है?"

2. Petitioner has filed claim petition alleging therein that he was appointed as Fitter in the year, 1994 by the Kangra Steels Pvt. Ltd., Nalagarh and he worked from 1994 to 28-5-1996. On 29-5-1996 when he reported for duty, he was asked to sign a good conduct bond. However, petitioner refused to do so. Thereafter, he was told that he should come and receive his full and final payment on 1-6-1996. On 1-6-1996, neither any notice was given to him nor he was paid the wages or retrenchment compensation. Therefore, his termination is illegal and bad in law and he is entitled to reinstatement alongwith back wages, continuity and seniority.

3. Respondent was duly served and Shri Dinesh Singh advocate put in appearance on behalf of the

respondent on two hearings. Thereafter, the service of the respondent was affected by way of affixation. However, respondent failed to appear in the Court and was proceeded against *ex-parte*. *Ex-parte* evidence was recorded. Petitioner while appearing in the witness box has alleged that he was working for the respondent from 21-7-1994 to May, 1996 and his services were terminated without any notice, retrenchment compensation. He was also not paid wages for two months. Therefore, he made a complaint to the Labour Officer, which is exhibited as Ex. P-1. He has mentioned that he be re-in-stated with full back wages and seniority.

4. I have considered the statement of the petitioner and also gone through the complaint Ex. P-1. The stand of the petitioner has been consistent that he was asked to fill a good conduct bond, which he refused and his services were terminated without giving him any notice and compensation or reason for his termination. In view of his statement which has remained un rebutted despite there being an opportunity, I hold that petitioner has proved his claim and is entitled to be re-instated in job *w. e. f.* 28-5-1996. He is also entitled to back wages and continuity of service from that date alongwith seniority in accordance with law. The reference is answered accordingly. A copy of this award be sent to appropriate government.

Announced in the open Court today this 13th Day of May, 2002.

Seal. (ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Labour Court, Shimla.

Ref. No. : 183 of 1998.

Instituted on : 11-9-1998.

Decided on : 14-5-2002

Shri Garibu Ram son of Shri Uday Ram, Village Kodewala, P. O. Haripurkhol, Tehsil Paonta, District Sirmaur.

Petitioner.

Versus

1. Divisional Manager, H. P. State Forest Corporation working Division Paonta Sahib, District Sirmaur.

2. Assistant Manager, H. P. State Forest Corporation, Forest working Division Paonta, Sahib, District Sirmaur.

Respondent.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioner: Shri Kuldeep Thakur, Advocate.

For respondents : Shri V. D. Khidta, Advocate.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate government:—

“कि क्या श्री गजेन्द्र राम कामगार को निर्वाचक प्रविजन मनेजर कोर्ट वरिष्ठ डिप्टिमेन्ट पावटा सहिब द्वारा 240 दिनों में ऊपर बताया नौकरी करने के उपरान्त नौकरी से निकाला जाना उचित एवं न्यायमय है, यदि नहीं तो उक्त अधिक कितने-कितने सेवा वर्षों व क्षतिपूर्ति का हकदार है?”

2. Petitioner in the claim petition has mentioned that he worked with the respondent as daily wager, beldar from 1982 to 1987 and completed 240 days of work in every calendar year. However, his services were dispensed with without serving him any notice and paying him any retrenchment compensation. It is also con-

tended that provisions of Section 25-G of the Industrial Disputes Act (In short as the 'Act') were also ignored as junior persons were engaged. Even fresh persons were given the employment by ignoring to provisions of Section 25-H of the act. Hence that, the petitioner is entitled to be re-instated in job with all consequential benefits and back wages. Petition is supported by an affidavit.

3. In the reply filed by the respondents, a preliminary objection has been taken that petition is barred as it has been filed after a lapse of more than 10 years. On merits, it is admitted that petitioner worked with the respondent from 1982 to 1987. However, it is denied that he completed 240 days in the calendar year of his service. A chart has been appended with the reply. It is also contended that petitioner left the job on his own. Lastly it is denied that any violation of Section 25-G and he has been made. Hence that the claim deserves to be dismissed.

4. Rejoinder was also filed. On the pleading of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 1-11-1999.—

1. Whether the termination of the petitioner is illegal in view of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 ? If so, its effect ?

2. Relief.

.. OPP.

FINDINGS

5. Issue No. 1. There is no dispute that petitioner worked with the respondent for all most 5 years *i. e.* from 1982 to 1987. The contention of the petitioner is that he completed 240 days of work in every calendar year, whereas it is denied by the respondent and it is mentioned that he has not completed required number of 240 days in any calendar year. The chart Ex. RA which has been produced by them has a different tale to tell. It shows that petitioner worked for 291 days in 1984, 278 days in 1985, 166 days in 1986 and 99 days in 1987. If this chart is read with the statement of the petitioner, it becomes clear that petitioner was in the employment of the respondent till April, 1987 and so, as per this chart only, prior to his disengagement, petitioner had put in more than 240 days of continuous service *i. e.* 99 days in 1987 and 166 days in 1986. Since the respondent has not given the mandays chart specifying the actual days of work put in each month, therefore, the only inference which can be drawn is that petitioner had completed 240 days of work in 1986-87 *i. e.* prior to his disengagement in the preceding 12 months, before that he had put 278 days in 1985 and 293 days in 1984. Therefore, even as per Ex RA the contention of the respondent that he did not complete 240 days is found to be incorrect.

6. The second question which arises is whether the petitioners abandoned the job himself or his services were terminated. No documentary or oral evidence has been led to prove that petitioner left the job himself. Rather RW has admitted that he did not know the petitioner personally nor he is aware of any such documentary evidence in this regard. Therefore, it cannot be made out from his statement that petitioner abandoned the job himself. Even the petitioner had left the job himself, it was required of the respondent to issue show cause notice to him for rejoining the duty or to have sought his explanation for wilful absence, once he has completed 240 days of employment in the preceding year. No such notice has been given and so it is not established that petitioner abandoned the job himself.

7. Another objection of the respondent is that petition has been filed after gap of 10 years. It is true that this reference has been received in the Court in the year 1998 and it may have taken one or two years before that, before the Conciliation Officer. However, since no

limitation is provided under the Industrial Disputes Act, therefore, petitioner has a right to claim the relief at this stage though Court has a discretion to mould the relief in view of the delay and laches on his part. Therefore, I hold that petitioner is entitled to re-instatement from the date of reference. He is not entitled to any back wages and he is entitled to continuity of service and seniority only from the date of reference in the Court. The issue is decided accordingly.

RELIEF

8. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the termination of the petitioner is illegal and I order his re-instatement with continuity and seniority from the date of reference in this Court, but without back wages. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate government for its publication.

Announced in the Open Court today this 14th Day of May, 2002.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,

Seal. H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court
Shimla

Ref. No.; 87/99

Shri Kuldeep Chand & Shri Prem Chand V/s M/s.
Dharampal. Satyapal Ltd., Solan (H. P.).

15-5-2002—Present—None for petitioner.

Mrs. Veena Sood Vice Shri
Rahual Mahajan Advocate for
Respondent.

Case called many time. It is 2.30 P. M. still none appeared for the petitioner. It seems that either the petitioner has settled the dispute or is not interested to pursue the petition. Since last 3 years, no claim has been filed. Therefore, in the absence of petitioner & statement of claim on record the reference is answered in negative. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Announced 15-5-2002.

Seal. Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. 56/98.

Decided on 23-5-2002

Shri Bhupinder Singh .. Petitioner.

Versus

M/s. Hitkari parties Ltd., Parwanoo, Solan.
.. Respondent.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

23-5-2002: Present.—None for the petitioner.

Shri V. K. Gupta AR for the respondent.

It has been stated at Bar by the Learned Counsel for the respondent that the petitioner has died and after that notice was issued to Shri Hem Raj who was representing the petitioner, which notice has been served on Sh. Hem Raj, but Shri Hem Raj is not present today.

Therefore, in view of the statement of Shri V. K. Gupta at Bar that petitioner has died & in view of the relief sought, which is personal to the petitioner, the reference stands answered in negative. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal. Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 260 of 1998

Instituted on: 10-12-1998.

Decided on: 23-5-2002.

Shri Ramesh Chand s/o Shri Mohan Lal, through
Mr. J. C. Bhardwaj, the General Secretary, H. P.
AITUC, Saproom, Solan. .. Petitioner.

Versus

1. Executive Engineer, HPSEB, Electrical Division,
Rajgarh.

2. The Assistant Engineer, H. P. S. E. B., Electrical
Sub-Division, Rajgarh, District Sirmaur

.. Respondent.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes
Act, 1947.

For petitioner: Shri J. C. Bhardwaj, AR.

For respondents: Shri S. P. Sharma, AR.

AWARD

Following reference has been received from the
appropriate Government .—

“Whether the termination of services of Shri Ramesh Chand by the Executive Engineer, H. P. State Electricity Board Division, Rajgarh, District Sirmaur H. P. w. e. f. 10-10-1998 without any notice, chargesheet, enquiry & without compliance of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified, If not, to what relief of service benefits, back wages, seniority and amount of compensation Shri Ramesh Chand is entitled to ?”

2. The claim petition pursuant to the reference has been filed by the petitioner alleging therein that he was working with the respondent from March, 1984 to October, 1988 when he was served a notice of retrenchment mentioning therein that he and others who were retrenched on that day will be called on the availability of the work. However, neither any proper notice nor any retrenchment compensation was paid. It is also submitted that the prior permission of the State Government was not obtained. Petitioner further submits that he completed more than 240 days of service in each calendar year. However, the compliance of Section 25-F, N. H. of the I. D. Act etc., was not made and his termination is illegal. It is submitted that petitioner is entitled to be re-instated with back wages and all consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondents, preliminary objection that there is no enforceable cause of action and that the petition is belated have been taken.

4. On merits, it is submitted that petitioner was engaged on daily wages basis w. e. f. 21-6-1985 and worked till 15-9-1988. It is also submitted that petitioner was casual in his work as per the mandays chart maintained by the respondent. It is also submitted that

the petitioner left the job on his own and his services were not terminated.

5. On the pleading of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 28-10-1999:—

1. Whether the termination of the petitioner is illegal in view of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 ? If so, its effect? OPP.
2. Relief.

FINDINGS

6. *Issue No. 1.* Petitioner while appearing in the witness box has maintained that he joined on 18-5-1984 and worked till 10-10-1988 when notice mark-A was served regarding the termination of his employment. He has also exhibited attendance roll for the year, 1986 which is EX. PA. Further he maintained that no compensation was paid to him at the time of retrenchment. Lastly that Dev Datt, Prem Kumar, Vidya Datt, Shayam Lal, Brij Mohan etc. who had been employed after him and were junior to him are still in the employment of the respondent. He has been given suggestion in the cross-examination that he used to be absent in between due to his private work, which he has denied. He has also been given suggestion that he did not give any thing in writing, which he admitted.

7. Shri Gian Chand Senior Assistant who has appeared on behalf of the respondent has mentioned that as per the record, petitioner worked from 21-6-1985 to 15-8-1988 and the statement is Exhibited as Ex. RA. He mentioned that thereafter petitioner abandoned the job. His cross-examination, however reveals that petitioner was terminated vide letter Ex. PX in which it is specifically mentioned that the work has finished and the petitioner will be called back as and when Naura Line work starts. The letter is dated 5-9-1988. He further admits that thereafter petitioner was not called though other beldars were kept after 1988. He also admits that petitioner was not given any retrenchment compensation. He also admits that as per Ex. RA. petitioner has worked for 333 days.

8. The details given in Ex. RA shows that petitioner was quite regular in his work and had completed the mandatory period of 240 days prior to his disengagement. Letter Ex. PX also shows that petitioner did not abandon the job rather he was terminated vide a written notice telling him that he will be re-called as and when work starts. Statement of RW shows that though new persons were employed after the termination of the petitioner, but he was not called. It is also clear from the statement of the RW that no retrenchment compensation was given to the petitioner. For all these reasons, it can be safely held that the termination of the petitioner is illegal, unjustified and is liable to be set-aside.

9. The next question which arises is "to what relief the petitioner is entitled." Though the wording of the reference reads that petitioner was terminated on 10-10-98. However it has come in the statement of the petitioner himself that he worked from 1984 to 1988. So there appears to be a wrong mention of the date in the reference. It is also clear from the statement of the petitioner that he did not make any representation in writing to any body after his termination. It has also not come in his statement that he made oral requests during this period for the re-employment. Therefore, his statement reveals that petitioner kept silent from 1988 till he raised the demand before the Conciliation Officer. Therefore, the petitioner remained sleeping over his right for all most 8 to 10 years. In these circumstances, the petitioner is not entitled to the back wages. He is only entitled to the seniority and continuity in service from the date of reference. I, therefore, hold accordingly.

RELIEF

10. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the termination of the petitioner

is illegal and is set-aside. Petitioner is entitled to seniority and continuity in service from the date of reference, but he is not entitled to the back wages. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government for its publication.

Announced in the Open Court today this 23rd Day of May, 2002.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-
Labour Court, Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Labour Court, Shimla.

Ref. No.: 8 of 1998.

Instituted on; 18-2-1998.

Decided on: 23-5-2002.

Shri Kuldeep Singh Patial S/o Shri Jaswant Singh Patial, r/o Village Kuthera, Haryalana, P. O. Nakron, Tehsil Amb, District, Una. *Petitioner.*

Versus

Continental Foundation Joint Venture, Nathpa Solding, P. O. Bhavanagar, District, Kinnaur through its Project Manager. *Respondent.*

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioners: Shri Rahul Mahajan, Advocate.

For respondent: Shri Rajnish Maniktala, Advocate.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate Government:—

"क्या मँसर्ज कान्दीनेन्टल फाउडेशन ज्वाइन्ट बैन्चर शोल्डिंग के प्रबन्धकों द्वारा श्री कुलदीप सिंह पटियाल को नौकरी से निकालना बँध है अथवा अबँध ? यदि अबँध है तो श्री कुलदीप सिंह पटियाल किस राहत व क्षतिपूर्ति का हकदार है ?"

2. Petitioner has alleged that he was working for CFJV w.e.f. 14-12-93 and was regularised w. e. f. 1-8-94. Further that he proceeded on sanctioned leave from 22-10-96 to 12-11-1996 and during this period he fell ill and so sent a telegram regarding his illness. However, a notice was issued to him by the management which was received by him on 18-12-1996 whereby he was directed to join his duties latest by 15-12-1996.

3. Petitioner contends that on receiving this letter, he proceeded to join the duties on 20-12-1996 though he was not completely fit and when he submitted his joining report on 21-12-1996, he was told that he stood already terminated w. e. f. 15-12-1996. It is submitted that management refused to receive his joining letter. Hence, the petitioner's services were terminated without taking into account the circumstances like illness. Hence, he is liable to be re-instated with all service benefits and back wages.

4. In the reply filed by the respondent preliminary objections have been raised that the respondent has been awarded a time bound project and the petitioner had been appointed for a fixed period of 18 months. It is also submitted that petitioner is not covered under the definition of retrenchment as his services stood terminated due to non renewal of contract on its expiry.

5. On merits, it is submitted that petitioner joined on 16-7-1994 and he proceeded on sanctioned leave for 21 days w. e. f. 22-10-96 to 12-11-96. Further that

petitioner did not join the duties, so a notice through registered letter dated 27-11-1996 was sent to the petitioner informing him that his absence beyond 13-11-96 was a misconduct as per the Certified Standing Orders and he was given an opportunity to report for duty by not later than 4-12-1996. It is further submitted that when he did not join even after the despatch of this letter, another opportunity was given to him and a registered letter dated 15-12-1996 was sent to him informing that he has been given final opportunity to report for duty immediately and not later than 15-12-1996, failing which it will be assumed that he is no longer interested to continue to work for respondent.

6. Respondent further submits that the registered letter should have normally been received within 3/4 days and that petitioner has wrongly mentioned that he received the second letter on 18-12-1996. It is submitted that as per the Certified Standing Orders any one who absents himself for 10 consecutive days or overstay leave beyond the period of leave originally granted or subsequently extended will be deemed to have left the service of the company. In view of this provision, the petitioner who was absent for such a long time, is assumed to have left the service *w. e. f.* 16-12-1996. So in view of the provision in certified standing orders, the order of termination was sent to the petitioner on 16-12-1996. However, this letter was returned with the remarks that 'the claimant has gone to the house of a relative and his family members did not give forwarding address'. It is submitted that sufficient opportunity has been given to the petitioner who stood terminated as per the Certified Standing Orders. Therefore, the petitioner's termination is legal and justified.

7. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 2-7-1999.—

1. Whether the termination of the petitioner is illegal in view of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. if so, its effect? .. OPP.

2. Relief.

FINDINGS

8. *Issue No. 1.*—Petitioner while appearing in the witness box has maintained that he joined the respondent on 14-12-1993 and was on sanctioned leave from 22-10-1996 to 11-12-1996. Further that he fell ill during this period and sent a telegram intimating the respondent that he will join as and when he is fit. Thereafter, he received a letter on 18-12-1996 whereby he was directed by the management to join the duties latest by 15-12-1996. He says that he reported for duty on 22-12-1996 and gave his medical fitness certificate Ex. PA. He was however told that his services stood terminated he was not allowed to join. He has exhibited the demand notice and one endorsement of Post Office, which is Ex. PC. *vide* which it reveals that record of the telegrams is kept for one year and is destroyed thereafter.

9. His cross-examination shows that he was appointed by letter Ex. RA for 18 months. He has also been confronted with leave application Ex. RB. He admits that he did not join thereafter. He also admits that a registered letter was sent on his home address on 27-11-1996, the copy of which is Ex. RC. He also admits that another letter was sent to him on 5-12-1996. The copy of which is EX. RD. However, he maintained that he did not receive the letter Mark-A though he admitted that this letter was also not received by his family members on the ground that he (petitioner) was not there. He admits that as per the company standing orders services are liable to be terminated for the absence of a workman for more than 10 days. He has been given suggestion that he has produced a false medical certificate.

10. In rebuttal of this evidence Shri Arjun Singh, Deputy-Manager Administration has appeared and men-

tioned that petitioner did not join after the sanctioned leave and so he was sent letter Ex. RC and RD through gistered post on the address supplied by the petitioner himself, but he failed to join the duties. So on 16-12-96, his services were dispensed with *vide* Ex. RW-1/B. This order was also sent through registered post. He has produced the receipt of this letter which was received back with the enforcement of the postal authorities that petitioner had gone to his relatives. He has given a suggestion that the copy of the telegram which was sent by the petitioner to the respondent regarding his illness was infact produced before the Conciliation Officer, however, respondent witness has expressed his ignorance. He has also admitted that no Enquiry Officer was appointed nor any enquiry was conducted. He has also been given suggestion that registered letter dated 5-12-1996 was only received by the petitioner on 18-12-1996. He has also been given suggestion that petitioner approached the Manager Administration alongwith the medical certificate on 21-12-1996, but he was allowed to join. Witness has expressed ignorance about these suggestion. This is the entire evidence.

11. I have heard the learned counsels of the parties and have also gone through the written arguments. The main thrust of the argument of the petitioner is that their cannot be any automatic termination of the service of a workman on the basis of Standing Orders and principles of natural justice have to be complied with. Which means that a show cause notice was to be served on the petitioner and a domestic enquiry was to be conducted. Therefore, since petitioner has been terminated on the basis of the Certified Standing Orders without affording him any opportunity, his termination is invalid and is liable to be set-aside. Reliance has been placed on (i) 1993 (3) Supreme Court cases 259, (ii) (1998) 6 Supreme Court Cases 538 & (iii) 2001-LLR-54-SC. On the other hand the contention of the respondent is that since despite two notices, which were duly served on the petitioner, he failed to join or sent any explanation. Therefore, no enquiry was required to be conducted. It is submitted that as per the Certified Standing Orders of respondent, as and when employee absents himself from the duty beyond a particular number of days, his services are liable to be terminated. As regards the principles of natural justice, it is submitted that an opportunity is required to be given to the workman to show cause for his absence. However, since despite two letters which were received by him. No explanation was offered by the petitioner, therefore, there was no need for conducting any enquiry. The respondent has placed reliance on AIR 2000 Supreme Court 2198.

12. In 1993(3) SSC-259, it has been held that automatic termination under the Certified Standing Orders is bad and principles of natural justice and duty to act in just, fair reasonable manner must be read into the Standing Orders. Therefore, the termination under the Certified Standing Orders without holding any domestic enquiry or affording any opportunity to the workman has been held to be violative of the principles of natural justice. It is held that duty of the respondent is to act fairly, and action should be impartial and fair. Similarly in (1998) 6 SCC-538, it has been held that the expression 'liable to automatic termination' occurring in the Standing Orders confers discretion upon the management to terminate services of a confirmed employee who had unauthorisedly overstayed leave. However, such discretion could not be exercised capriciously and the principles of natural justice have to be read into the relevant clause and therefore, circumstances leading to unauthorised absence have to be ascertained before resorting to termination. Lastly in 2001 LLR-54, again Hon'ble Supreme Court has held that even when a workman fails to report for duty, the management cannot presume that the workman has left the job. It is imperative to follow the principles of natural justice by giving the opportunity.

13. So the stress of all these authorities cited above is that irrespective of the provisions in Certified Standing Orders that the service of a workman for remaining on

un-authorised leave beyond a certain period will amount to automatic termination, no such termination can be held valid unless and until principles of natural justice are followed and due opportunity is given to the petitioner to explain the reasons for his un-authorised absence. More or less, the same principle has been upheld by Hon'ble Supreme Court in AIR-2000-SC-2198, which is relied upon by the respondent. The facts of the case before Hon'ble Supreme Court were that a bank employee remained absent for more than 90 days and a show cause notice was sent to him to report for work before a particular date, failing which he would be deemed to have voluntarily retired from the services of the Bank. The notice was sent on the correct address however, the employee did not appear despite such notice. It was held that under a bipartite settlement, it was rightly held that delinquent had voluntarily retired from the service of the bank. It was observed by Hon'ble Supreme Court that under these circumstances, it was not necessary for the bank to hold an enquiry before passing the order. Further that an enquiry could have been necessary if delinquent had submitted his explanation, and if it was not acceptable to the Bank or had contended that he reported for duty but was not allowed to join by the bank. Hon'ble the Apex Court has further held.

"The requirements of principles of natural justice, which are required to be observed are: (1) workman should know the nature of the complaint or accusation; (2) an opportunity to state his case; and (3) the management should act in good faith which means that the action of the management should be fair, reasonable and just."

14. So, irrespective of the fact that this authority has been relied by the respondent this authority lays down that the delinquent workman cannot be terminated for remaining on un-authorised leave without affording him any opportunity as per the principles of natural justice. The distinguishing features between the authority cited by the respondent is that petitioner in that case had not alleged that he had submitted his joining report, but was not accepted by the management. The Hon'ble Supreme Court has highlighted that:

"An enquiry would have been necessary if delinquent had submitted his explanation which was not acceptable to the Bank or contended that he did report for duty but was not allowed to join the Bank."

(Emphasis supplied)

Meaning thereby that if the Bank employee had offered his joining report which was not accepted then he was entitled to a domestic enquiry. Now coming to the facts of the present case, petitioner has alleged that he received the registered letter on 18-12-1996 and immediately left his house for joining the duties. He did submit his joining report and the medical certificate to the Administrative Manager, who refused to accept these documents. This suggestion has been categorically given to the RW, who has not denied the suggestion and has merely expressed his ignorance. Therefore, there is no hesitation in holding that petitioner did submit his joining report may be after the expiry of the time allowed by the respondent. He did offer his explanation by way of medical certificate, so it was incumbent on the management to hold an enquiry into the matter. Moreover, it is not proved that the letter which was despatched on 6th or 7th December, 1996 was in fact received prior to 15-12-1996 and not on 18-12-1996. There is no presumption that registered letter will definitely reach the destination within 3/4 days, rather the registered letters are known to take long time to reach the destination some times. Therefore, there cannot be any presumption that petitioner having the knowledge of the final date of joining did not join by 15-12-1996. So in these circumstances, it was essential to hold a domestic enquiry in the matter and the

services of the petitioner could not be terminated merely on the basis of the Certified Standing Orders. I therefore, hold that the termination of the petitioner is unjustified, illegal and liable to be set-aside.

15. There is no evidence from either of the side that petitioner was gainfully employed during this period, neither petitioner has mentioned that he was un-employed during this period nor any suggestion has been given that he was gainfully employed. In these circumstances, I hold that petitioner is not entitled to the back wages, but he is entitled to the seniority and continuity of service from the date of termination. The issue is decided accordingly.

RELIEF

16. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that petitioner is entitled to continuity and seniority in service from the date of his termination, but without back wages. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate Government for its publication.

Announced in the Open Court today this 23rd May, 2002.

Sd/-
Seal. (ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-
Labour Court, Shimla.

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2002

No. Shram (A) 7-1/2002.—In exercise of the powers vested in him under section 17(I) of the Industrial Dispute Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards in the Rajpatra announced by the Presiding Officer, Labour Court, H.P. of the following cases:—

S. No.	Ref. No.	Particulars	Section	Remarks
1.	Ref. No. 116/2001-Shri Mohinder Singh Vs. M. D. M/s Globe Precision Industries Baddi.	-10-	Publication	
2.	Ref. No. 114/2001-Shri Baljeet Singh Vs. M.D. M/s Globe Precision Industries Baddi.	-10-	-do-	
3.	Ref 113/2001-Shri Rajender Singh Vs. M. D. M/s Globe Precision Industries Baddi.	-10-	-do-	
4.	Ref. No. 109/2001 Shri Madan Singh Vs. M. D. M/s Globe Precision Industries Baddi.	-10-	-do-	

By order,
Sd /
Principal Secretary (Lab. & Emp.),
to the Government of Himachal Pradesh.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla

Ref. 116/2001.

Sh. Mohinder Singh .. Petitioner.

Vs.

M. D. M/s Globe Precision [Industries (P) Ltd.
Baddi. .. Respondent.

Reference Under Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947.

29-6-2002: Present : None for the petitioner.

Sh. V. K. Gupta AR for the respondent.

Case called many times. It is 2.15 PM. Still not appeared. Neither the petitioner is present nor statement of claim is on record. In the absence of the petitioner and statement of claim, the reference is dismissed for non prosecution. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR)
Presiding Judge, H.P. Industrial
Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 114/2001.

Sh. Baljeet Singh .. Petitioner.

Vs.

M. D. M/s Globe Precision Industries (P) Ltd.
Baddi. .. Respondent.

Reference Under Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947.

29-6-2002: Present :—None for the petitioner

Sh. V. K. Gupta AR for the respondent.

Case called many times. It is 2.15 P.M. Still not appeared. Neither the petitioner is present nor statement of claim is on record. In the absence of the petitioner and statement of claim the reference is dismissed for non prosecution. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge, H.P. Industrial
Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 113/2001.

Sh. Rajinder Singh .. Petitioner.

V/s

M.D.Ms. Globe Precision Industries (P) Ltd. Baddi.
.. Respondent.

Reference Under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

29-6-2002:—Present: None for the petitioner.

Sh. V. K. Gupta AR for the respondent.

Case Called many times. It is 2.15 PM. Still not appeared. Neither the petitioner is present nor statement of claim is on record. In the absence of the petitioner and statement of claim the reference is dismissed for non prosecution. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor Presiding
Judge, H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour, Court,
Shimla

Ref. 109/2001.

Sh. Madan Singh .. Petitioner.

V/s

M. D. M/s Globe Precision Industries (P) Ltd.
Baddi .. Respondent.

Reference Under Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947.

29-6-2002:—Present: None for the petitioner.

Sh. V. K. Gupta AR for the respondent.

Case called many times. It is 2.15 PM. Still not appeared. Neither the petitioner is present nor statement of claim is on record. In the absence of the petitioner and statement of claim, the reference is dismissed for non prosecution. Let a copy of his order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2002

No. Shram (A)7-1/2002.—In exercise of the powers vested in him under section 17(I) of the Industrial Dispute Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards in the Rajpatra announced by the Presiding Officer, Labour Court, H.P. of the following cases:—

S. No. 1	Ref. No. 2	Particulars 3	Section 4	Remarks 5
1.	Ref. No. 44/1999-Shri Ranjit Singh Vs. M/s United Diamonds Ltd. Unit No. 1, Parwanoo.	-10-	Publica- tion	
2.	Ref. No. 45/2000-Shri Sita Ram Vs. M/s Hira Filters Ltd. Baddi.	-10-	-do-	
3.	Ref. No. 176/1998-Shri Dilbag Singh Vs. M/s Ashoka Spanners Ltd. Baddi.	-10-	-do-	
4.	Ref. No. 251/1998-Smt. Sheela Devi Vs. Neutricial Snaks Kasauli Road Parwanoo, Distt. Solan.	-10-	-do-	
5.	Ref No. 178/1998-Smt. Savitri Devi Vs. M. D. M/s Neutricial Ranex Kasauli Road, Parwanoo.	-10-	-do-	
6.	Ref. No. 179/1998-Smt. Nisha Devi Vs M.D. Rabbar Services Ltd. Poly No. 2 Parwanoo.	-10-	-do-	
7.	Ref. No. 155/1998-Smt. Usha Kashyap Vs. Principal M.R.A. D.A.V. School Rajgarh.	-10-	-do-	
8.	Ref. No. 264/1998-Shri Ram Bahadur Vs. M/S J.K. Leatherite Ltd. Industrial Area Baddi.	-10-	-do-	
9.	Ref. No. 185/1998-Shri Dharam Singh Vs. D. F. O. Solan.	-10-	-do-	
10.	Ref. No. 40/1999-Workers Union Vs. M/s Surya Steel Industrial Sidhartha Steel Industries. Solan.	-10-	-do-	
11.	Ref. No. 130/2001-Shri Om Prakash Vs. I & PH Sunni	-10-	-do-	
12.	Ref. No. 167/2001-Shri Jagdish Chand Vs. HPSEB Chopal.	-10-	-do-	
13.	Ref. No. 13/2001-Mohd Suleman Vs. M/S Asia Resorts Ltd.	-10-	-do-	
14.	Ref. No. 179/2000-Shri Nazir Hussain Vs. Asia Resorts Ltd. Parwanoo.	-10-	-do-	
15.	Ref. No. 169/2000-Him Neel Breweries Employees Union Vs. Mgt of unit.	-10-	-do-	

1	2	3	4
16.	Ref. No. 24/1998-Shri Sunder Singh Vs. HPPWD Haripur-dhar.	-10-	Publication.

By order,

Sd/-
Principal Secretary.In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 44/99.

Sh. Ranjeet Singh .. Petitioner.

Vs.

M/s United Diamonds Ltd. Unit No.1, Parwanoo

.. Respondent.

Reference Under Section 10 of the Industrial
Dispute Act, 1947.

10-6-2002:—Present:—None.

The case called many times. It is 2.30PM. Still none appeared for the petitioner. Since 1999 neither the claim is on record nor petitioner is coming forward to pursue his claim service of both petitioner as well as respondent has been affected through affixation. It seems that either the petitioner has settled his dispute or is not interested to pursue the matter. In the absence of statement of claim or evidence, the reference is answered in negative. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal -cum-Labour
Court, Shimla.In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 45/2000.

Sh. Sita Ram and other .. Petitioner.

Vs.

M/s Hira Filters (P) Ltd. Baddi .. Respondent.

Reference Under Section 10 of the Industrial Dis-
pute Act, 1947.

11-6-2002:—Present:—None for the petitioner.

Sh. K. C. Arya, AR for the respondent.

The case called many time. It is 3.00 PM. Still none appeared for the petitioner. Neither any rejoinder is filed nor the petitioner is present today. It seems that the petitioner is not interested to pursue the petition. In the absence of the petitioner and his evidence, the reference is answered in negative. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.In the Court of Smt. Aruna Kapoor Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

R-176/98

Sh. Dilbag Singh

Vs.

M/s Ashoka Spanners Pvt. Ltd. Baddi.

12-6-2002 :—Present : None for petitioner.
Sh. Sanjay Kumar Adv. for respondent.

Case called thrice. None has appeared for petitioner. It seems that the petitioner is not interested to pursue the petition. Hence reference is answered in negative for want of prosecution. Let a copy of this order be sent for publication in accordance with Law.

Sd/-
Seal. (ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-
Labour Court, Shimla.In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 251/98.

Smt. Sheela Devi

Vs.

M/s Neutricial Snaks Kasauli Road, Parwanoo,
Distt. Solan, H.P.

13-6-2002

Present

None
Be called again

13-6-2002:—Present:—None.

Case called many times. It is 2.45 P.M. Still none appeared for the petitioner. It seems that either the petitioner has settled the matter or is not interested to pursue the matter. In the absence of petitioner and his evidence, the reference is answered in negative and dismissed in default of the appearance of the petitioner. Let a copy of this order be sent to appropriate Government. The case file after its completion be consigned to record room.

Sd/-
Seal. (ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 178/98

Smt. Savitri Devi .. Petitioner.

Vs.

M. D. M/s Neutrical Ranex Kasauli Road Sec.-IV
Parwanoo, Distt. Solan .. Respondent.Reference under section 10 of the Industrial Disputes
Act, 1947.

13-6-2002:—Present: None.

The case called many times. It is 2.05 P.M. Still none appeared for the petitioner. It seems that either the petitioner is not interested to pursue the claim or has settled the matter. In the absence of the petitioner and evidence, the reference is dismissed in default of the appearance of the petitioner. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 179/98

Smt. Nisha Devi .. Petitioner.

Vs.

M. D. Jal Rabbar Service Pvt. Ltd. Poly No. 2
Parwanoo .. Respondent.

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

13-6-2002:—Present: None.

Case called many times. It is 2.15 P. M. Still none appeared for the petitioner. It seems that either the petitioner has settled the matter or is not interested to pursue the matter. In the absence of petitioner & his evidence, the present reference is dismissed in default of the appearance of the petitioner. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal. Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.

In the Court of Presiding Judge, H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. 155/98.

Smt. Usha Kashyap

Vs.

Principal, M. R. A. D. A. V. School, Rajgarh.

18-6-2002:—Present: None for petitioner.

Sh. Bed Ram, AR for Respondent.

The case called many times. It is 2.35 P. M. Still none appeared for the petitioner. Despite opportunity, nor any evidence has been produced. In the absence of petitioner & his evidence, the present reference is answered in negative for non prosecution. Let a copy of his orders be sent to appropriate Government.

Seal. Sd/-
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

Ref. No. 264/98.

Sh. Ram Bahadur Singh .. Petitioner.

Vs.

M/s J.K. Leatherite Ltd. Industrial Area Baddi,
Distt. Solan .. Respondent.

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

20-6-2002:—Present: None.

The case called many times. It is 2.30 P.M. Still none appeared for the petitioner neither statement of claim has been filed since 1998 nor evidence has been list. In the absence of statement of claim & evidence on record the reference is answered in negative for non-prosecution. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal. Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Presiding Judge, (H. P.) Industrial Tribunal-cum-Labour Court Shimla

Shri Dharam Singh Vs. D.F.O., Solan.

24-6-2002 Present:

Ref. No. 185/98.

Shri J. C. Bhardwaj for the petitioners.
Shri Basant Lal for the respondents.

Petitioner not present. A number of opportunities have been given to petitioner. But no evidence is being examined. Even the petitioner is not present. Shri Bhardwaj has stated that he has informed the petitioner number of times but he is not turning up.

In view of this, petitioner does not seem to be interested in pursuing the claim. Hence reference is answered in negative for non-prosecution.

The copy of this order be sent for publication in the official Gazette.

Seal. Sd/-
Presiding Judge, H.P.
Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.

In the Court of Presiding Judge, (H.P.) Industrial Tribunal-cum-Labour Court Shimla

Workers Union Vs. M/s Surya Steel Industries/
Sidhartha Steel Industries, Deonghat, Distt. Solan,
H.P.

Ref. No. 40/99.

24-6-2002 : Present : None for the petitioner.

Shri Vipul Parbhakar, Advocate for Respondent.

Case has been called repeatedly. None has appeared for the petitioner.

The order sheet reveals that claim is not being filed, despite various opportunities. Today neither the petitioner nor his A/R are present nor the claim petition has been filed. Hence it appears that petitioner does not want to pursue the claim. Hence reference is answered in negative for non-prosecution of the claim.

The copy of this award be sent for publication in Rajpatra.

Seal. Sd/-
Presiding Judge, H.P.
Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. 130/2001

Sh. Om Prakash .. Petitioner.

Vs.

Ex. Engg. I & PH Divi. Suni .. Respondent.

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

25-6-2002:—Present: None.

Case called thrice. It is 2.00 P.M. None has appeared on behalf of any of the party. It seems that both parties have settled the dispute or petitioner is not interested in the matter. Reference is answered in negative. Let a copy of this order be sent for publication.

Seal. Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour,
Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. 167/2001

Sh. Jagdish Chand

Petitioner.

Vs.

HPSEB Divi. Chopal, Distt., Shimla

Respondent.

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

26-6-2002:—Present:—None.

Case called many time. It is 2.30 P.M. Still none appeared for the petitioner. Neither the statement of claim is on record nor petitioner or his counsel has appeared. In the absence of petitioner, the reference is answered in negative for non-prosecution. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal. ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Presiding Judge, H. P. Industrial
Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. 13/2001

Mohd. Suleman

Vs.

M/s Asia Resort Ltd. Parwanoo

26-6-2002:—Present:—None for the Petitioner.
Sh. V. K. Gupta, AR for Respondent.

Case called many times. It is 2.30 P.M. Still none appeared on behalf of Petitioner. Neither the Petitioner is present nor any claim has been field since 16-4-2001. Hence the reference is answered in negative for non-prosecution. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal. Sd/-
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum
Labour Court, Shimla.

In the Court of Presiding Judge, H. P. Industrial
Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. 179/2002

Nazir Hussain Vs. Asia Resorts Ltd. Parwanoo

26-6-2002:—Present:—None for petitioner,
Shri V. K. Gupta, AR for Respondent.

Case called many times. It is 2.15 P.M. Still none appeared on behalf of petitioner. Neither the petitioner is present nor any claim has been field since 16-4-2001. Hence the reference is answered in negative for non-prosecution. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Announced
18-6-2002.

Seal. Sd/-
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-
Labour Court Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. 169/2000.

Him Nool Breweries Employees Union

Petitioner.

Vs.

Mgt. of Unit

Respondent.

Reference Under Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947.

2-7-2002.—Present.—Sh. K. K. Dixit, AR for the petitioner.

Sh. R. P. Kapoor, AR for the respondent.

Ars for both the parties have filed an agreement on record which is Ex. PX alongwith the oral statement made in the court that the term of reference referred to this Court have been settled by them amicably and prayed for the withdrawal and dismissal of the reference has having been fully satisfied.

In view of the Statement made on oath in the Court and the agreement Ex. Px filed in the Court, the present reference is answered accordingly. Let a copy of this order be sent to the appropriate Government for its publication.

Seal. ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge,
H. P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 24 of 1998.

Instituted on : 18-3-1998

Decided on : 3-7-2002

Shri Sunder Singh Beldar C/o Shri J. C. Bhardwaj,
the General Secretary, AITUC, Saproon-Solan
Petitioner.

Versus

The Exocutive Engineer, HPPWD Division Haripur-
dhar, Distt. Sirmaur. H.P. Respondent.

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioner : Shri J. C. Bhardwaj, AR.

For respondent ; Shri R. K. Sharma, AR.

AWARD

1. The following reference has been received from the appropriate Government ;—

‘कि क्या श्री सुन्दर सिंह बेलदार को अधिनासी अधिनस्त (हि0 प्र0) लोक निर्माण विभाग मण्डल हरिपुर धार, जिला सिरमौर द्वारा बिना नोटिस एवं मूआबजा दिए नौकरो मे बर्खास्त करना न्यायसंगत है यदि नहीं तो कामभार किम क्षति प्रति एवं लाभ का हकदार है?’

2. Petitioner has alleged that he was employed as beldar by the respondent and worked as such for more than 240 days for two years. However, his services were disengaged. He kept on meeting the Departmental Officers for re-engagement and he was given re-employment on 1-9-94 against a vacant post of Beldar, but then

again his services were terminated on 26-2-1995. It is submitted that petitioner has been terminated illegally in violation of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short as the 'Act'). Hence he is entitled to re-instatement with consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondent, preliminary objections have been taken that no fundamental and legal rights of the petitioner have been infringed. Secondly that petition has been filed after a delay of three years. Therefore, it is belated. It is also contended that the petition is bad for non joinder of the necessary parties as his employer is the State Government and not the Executive Engineer.

4. On merits, the plea of the respondent is that petitioner left the job on his own and was not terminated. Hence, the petition is bad and be dismissed.

5. I may point out that though originally the petition was filed against the Executive Engineer, but later on, the same was amended and the State of Himachal Pradesh through Secretary, PWD was arrayed as the Respondent.

6. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 2-1-1999:—

1. Whether the termination of the petitioner is bad in view of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947? If so, its effect?

OPP.

2. Relief.

FINDINGS :

7. Issue No. 1.—Petitioner has stepped in the witness box in support of his case and mentioned that he joined the respondent in February, 1985 and worked till December, 1987. He also mentioned that he completed more than 240 days in each calendar year. Thereafter he was removed. He again approached the JE and the SDO concerned, but to no avail. He was however re-employed by the Department in November, December, 1994 and then terminated in February, 1995. He has mentioned that no notice was given to him nor any Compensation was given to him. Further that junior persons were retained.

8. Despite opportunity, no cross-examination has been done on this witness. The respondent has also not appeared in the witness box and has only tendered one document Ex. R-1 in support of their plea.

9. The document Ex. R-1 which has been tendered by the respondent shows that from February, 1985 till December, 1987, petitioner was working with respondent had put in 190 days in 1985, 283 days in 1986 and 290 days in 1987. Further thereafter, he put in 57 days in November and December, 1994 and 44 days in the months of January and February, 1995. This chart Ex. R-1 fully support the contention of the petitioner regarding his actual working days. The plea of the petitioner is that he was terminated and his juniors were retained by the respondent. No cross-examination has been conducted on the petitioner, which means that his statement on oath in this regard has been accepted by the respondent. This also shows that petitioner kept on approaching the department for employment, but instead junior persons were given employment. In these circumstances, the claim of the petitioner is fully proved and it is established on record that his services have been terminated without complying with the provisions of Section 25-F & 25H of the act. It is also established that though junior persons were retained and re-employed, but the petitioner despite oral representation was not given any employment by the Department. I, therefore, hold that the termination of the petitioner is bad in law and he is entitled to re-instatement in service.

10. Petitioner has mentioned that he was given re-employment for about three months from November, 1994 to February, 1995 and thereafter again he was

terminated. The petitioner is therefore, entitled to continuity of service and also seniority from February, 1995. He however, is held entitled to the wages @ 25% of his last pay drawn from the date of reference. Hence, the issue is decided accordingly.

RELIEF :

11. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the petitioner is entitled to re-instatement in job from February, 1995 with seniority and continuity in service with back wages to the extent of 25% from the date of reference. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate Government for its publication.

Announced in the Open Court today this 3rd July, 2002.

Seal.

ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal -cum-Labour Court,
Shimla.

योजना विभाग

अधिसूचना

जिमला-2, 14 अगस्त, 2002

संख्या पी० एल० जी० एफ० सी० (एफ) 1-9/94-131-खण्ड-III.—
यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामित गांव उप-महाल तियूडी-प्रथम, तहसील एवं जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन (ऊना से चुरू तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए योजना की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांकन समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन, सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : ऊना	तहसील : ऊना	रकबा (हेक्टेयर में)
गांव	खसरा नं०	
1	2	3
उप-महाल तियूडी-प्रथम	1116/1	0 14 94
	1116/2	0 02 44
	1131/1	0 00 05
	1141	0 06 94
	1142	0 00 34
	1150/2	0 00 24
	1151/2	0 00 21
	1158	0 00 38
	1159	0 00 17
	1161	0 00 22
	1166/2	0 10 28
	1167/2	0 00 12
	1168/1	0 00 08
	1170/1	0 01 12
	1194/3	0 07 40

1	2	3
	1195/1	0 28 72
	1195/3	0 00 35
	1197/2	0 03 85
	1198/1	0 00 23
	1200/3	0 23 48
	1201/1	0 01 77
	1202/2	0 10 88
	1204/1	0 04 62
	1206/1	0 00 34
	1207/1	0 01 20
	1210/2	0 00 34
	1221/1	0 02 43
	1232/1	0 01 25
	1233/2	0 01 24
	1235/2	0 00 54
	1236/2	0 00 66
	1239/2	0 36 06
	1244	0 04 99
	1245/2	0 15 59
	1247/1	0 11 15
कुल .. 35		1 95 17

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव ।राजस्व विभाग
(प्रोजेक्ट सेल)

अधिसूचना

जिमला-171 002, 28 जुलाई, 2002

संख्या रेव (पी0 डी0) ई0 (1)-1/94.—इस विभाग के सम्मेल्यक अधिसूचना, दिनांक 15-10-2001 की निरन्तरता में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला स्तरीय वासपा हाईडल परियोजना विस्थापित पुनर्वास एवं सलाहकार समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करने के सहर्ष आदेश देते हैं :-

1. श्री राजमन सिंह नेगी, गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर । गैर-सरकारी सदस्य
2. श्री पदम सिंह नेगी, गांव व डाकघर रामनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर । तदैव
3. श्री तेजबन्त सिंह नेगी, गांव व डाकघर कित्वा, तहसील सांगला । तदैव
4. श्री विनय सिंह नेगी, गांव व डाकघर सापनी, तहसील सांगला । तदैव
5. श्री भूपेन्द्र सिंह नेगी, गांव व डाकघर बुया, तहसील सांगला । तदैव
6. भारत भूपण नेगी, गांव व डाकघर भोग, तहसील सांगला । तदैव
7. श्रीमती चन्द्रमणी पत्नी श्री राम सिंह, गांव व डाकघर चासु । तदैव

2. उपरोक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति में सम्बन्धित कार्य के लिए की गई यात्रा भत्ता/माईलेज/दैनिक भत्ता नियमानुसार देय होगा ।

3. सरकारी सदस्यों को उन पर लागू यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा ।

4. उपायुक्त किन्नौर गैर-सरकारी सदस्यों के नियन्त्रण अधिकारी होंगे और यात्रा भत्ता जिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे ।

5. यात्रा भत्ते का चर्चा मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-03-जिला स्थापना 01-सामान्य स्थापना यात्रा भत्ता में देय होगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

जिमला-9, 8 अगस्त, 2002

संख्या आर0 डी0-1-बी0 (3) 2/92-99-5-1088.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी, राजपत्रित श्रेणी-I को उनकी सरकारी सेवा में अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से सेवा निवृत्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं :-

क्र० सं०	सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी का नाम व तैनाती स्थान	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1.	श्री आर0 पी0 सिंह, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर ।	24-1-45	31-1-2003
2.	श्री राम दास, खण्ड विकास अधिकारी, पांगी, विकास खण्ड पांगी ।	19-3-45	31-3-2003
3.	श्री चैत सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़ ।	27-5-45	31-5-2003
4.	श्री हंस राज शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कण्डाघाट ।	14-6-45	30-6-2003
5.	श्री चरण दास, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट ।	1-7-45	31-7-2003
6.	श्री वंसी लाल, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब ।	15-8-45	31-8-2003
7.	श्री रणजीत सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निरमण्ड ।	17-8-45	31-8-2003

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

भाग-2—वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्याओं और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

—शून्य—

भाग 3.—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैशियल कमिशनर तथा कमीशनर ऑफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

अधिसूचना

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

शिमला-171002, 22 जून, 2002

संख्या पब0 ए0 (3) 27/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब0 ए0 (3) 5/94, तारीख 29-1-1997 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अधिक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-II (राजपत्रित) के पद में भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अधिक्षक ग्रेड-I, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग अधिक्षक ग्रेड-I, वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है के संक्षिप्त नाम में शब्द, चिन्ह और रोमन अंक “वर्ग-II” के स्थान पर वर्ग-I शब्द चिन्ह और रोमन अंक प्रस्थापित किए जाएंगे।

3. उपाबन्ध “अ” का संशोधन.—उक्त नियमों के उपाबन्ध “अ” में:—

(क) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“वर्ग-I (राजपत्रित)”।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No. Pub. A (3) 27/99, dated 22-6-2002 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

**INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS
DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd June, 2002

No. Pub. A (3) 27.99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Superintendent Grade I (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. Pub. A (3) 5/94, dated 29-1-1997, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Superintendent Grade-I

2. *Amendment of Short Title.*—In short title of the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Superintendent Grade I (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 (hereinafter referred to as the “said rules”) for the word, sign and Roman figure, “class-II”, the word sign and Roman figure, “Class-I” shall be substituted.

3. *Amendment in Annexure “A”.*—In Annexure “A” to the said rules:—

(a) For the existing entries against Column No. 3 the following shall be substituted, namely:—

“Class-I Gazetted.”

By order,

Sd/-
Comm.-cum-Secretary.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 2002

संख्या 2-10/93-अम.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 9-9-1998 तथा 18-10-2000 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिक्षक ग्रेड-I, वर्ग-II (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, अधिक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, अधिक्षक ग्रेड-I, वर्ग-II (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के संक्षिप्त नाम में शब्द, चिन्ह और रोमन अंक “वर्ग-II” के स्थान पर “वर्ग-I” शब्द चिन्ह और रोमन अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उपाबन्ध “क” का संशोधन.—उक्त नियमों के उपाबन्ध “क” में:—

(क) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।”

(ख) स्तम्भ संख्या 5 के सामने विद्यमान उपाबन्धों में शब्द “अचयन” के स्थान पर “चयन” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (ग) स्तम्भ संख्या 12 के सामने विद्यमान उपाधियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
“विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।”

अदेश द्वारा,

हरिन्द्र हीरा,
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No. 2-10/93-Shram, dated 11-6-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th June, 2002

No. 2-18/93-Shram.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Labour and Employment Department, Superintendent Grade-I, Class-II (Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified vide this department Notification of even number, dated 9-9-1998 and 18-10-2000, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Labour and Employment Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted), Ministerial Services, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Short Title.*—In short title of the Himachal Pradesh Labour and Employment Department, Superintendent Grade-I, Class-II (Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 1998 (hereinafter referred to as the, “said rule”) for the word, sign and Roman figure “Class-II” the word, sign and Roman figure, “Class-I” shall be substituted.

3. *Amendment of Annexure “A”.*—In Annexure “A” to the said rules:—

- (a) For the existing provisions against Col. No. 3, the following shall be substituted, namely :—
“Class-I (Gazetted) Ministerial Services.”
- (b) For the existing Provisions against Col. No. 5, for the word “Non Selection” the word “Selection” shall be substituted; and
- (c) For the existing provisions against Column No. 12 the following shall be substituted, namely :—

“D. P. C. to be presided over by Chairman, H. P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.”

By order,

HARINDER HIRA,
Principal Secretary.

अम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

Secretary, Himachal Pradesh Private School Shikshak Mazdoor Sangh (Affiliated to BMS) Branch Palampur, District Kangra (H.P.) and the Principal, D. A. V. Public School, Palampur, District Kangra (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश की नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the strike w. e. f. 24-6-2002 by the workmen of the D. A. V. Public School, Palampur, District Kangra H. P. for not implementing the terms number 1, 2, 3 and 6 of the settlement under Industrial Disputes Act, 1947 dated 21-3-2001 (copy enclosed at annexure-A) on the demand notice raised by workers union Himachal Pradesh Private School Shikshak Mazdoor Sangh (affiliated to BMS), Palampur, District Kangra, H. P. is legal and justified ? If yes, its effects ?”

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-1/85 (लेव0) आई0 डी0 कांगड़ा.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Yash Pal s/o Shri Prithvi Singh and others (13) workmen as per annexed over leaf and the 1. Shri Ashok Kumar Aggerwal, Partner M/s. Leader Rubber Industries, Damtal, District Kangra (Present address) M/s Agra Spinning, Damtal, District Kangra, H. P., 2. Sh. Satnam, Partner, M/s Leader Rubber Industries, Damtal (Present address) M/s Himcold Tyre Industries, Damtal District Kangra, H. P., 3. Sh. Dharm Pal Partner M/s Leader Rubber Industries, Damtal (Present Address) M/s Agra Stone Crusher, Damtal, District Kangra, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश की नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the action of Management M/s Leader Rubber Industries, Damtal to closed down the factory w. e. f. 13-4-2001 without complying the

संख्या 11-1/85 (लेव0) आई0 डी0 कांगड़ा/2002/Kangra.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि President/General

provision of the section 25-FFF of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits backwages, seniority and amount of compensation (14 workmen) as per annexure over leaf are entitled to?"

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

कामगारों की सूची :

1. श्री जश पाल सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंह, गांव सनौर, डाकखाना छडगढ़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि 0 प्र 0) ।
2. श्री किशन चन्द सुपुत्र श्री रूद्र राम गांव व डाकखाना मोहतली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
3. श्री प्रवीन सुपुत्र श्री हरि सिंह, गांव व डाकखाना मोहतली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
4. श्री विजय सिंह सुपुत्र श्री अमर सिंह, गांव सिरय, डाकखाना डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
5. श्री अयान सिंह सुपुत्र श्री अमर सिंह, गांव सिरय, डाकखाना मोहतली तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
6. श्री गुलाब सिंह सुपुत्र श्री लाल साह, गांव व डाकखाना मोहतली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
7. श्री रश पाल सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंह, गांव चक्काड़ी, डाकखाना राजा-का-तालाब, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
8. श्री बाबू राम सुपुत्र श्री चतरा राम, गांव व डाकखाना सुरडमा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
9. श्री केशर दास सुपुत्र श्री केशर राम, गांव खम, डाकखाना आर एसपुरा, जम्मू ।
10. श्री गुरदयाल सिंह सुपुत्र श्री जैसी राम, गांव व डाकखाना सुरडमा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
11. श्री राजू सुपुत्र श्री धेरू शाह, गांव व डाकखाना मोहतली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
12. श्री नानक चन्द सुपुत्र श्री लाल शाह, गांव व डाकखाना मोहतली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
13. श्री देश राज सुपुत्र श्री हरि चन्द्र, गांव चक्कातावर, डाकखाना गोन्दला, तहसील आर एसपुरा, जम्मू ।
14. श्री जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री धनी राज, गांव व डाकखाना सिरय, तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

शिमला-171001, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-1/85 (लेब 0) आई 0 डी 0 भाग/2002/कांगड़ा.—अधो-हस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Seema Devi w/o Sh. Amar Nath, Village Chanani, P. O. Bhali, Tehsil Jawali, District Kangra, H. P. and The Principal, International Sahaja Public School, Talnoo, Dharamshala Cantt, District Kangra H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिये भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the service of Smt. Seema Devi w/o Shri Amar Nath w.e.f. 5-8-2001 by the Principal, International Sahaja Public School, Talnoo, Dharamshala District Kangra H. P. without following the provision of Industrial Dispute Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief of service benefits, the above worker is entitled to?"

सं 0 11-2/93 (लेब 0) आई 0 डी 0 भाग/2002/सोलन.—अधो-हस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Mohinder Singh s/o Shri Jagmal Singh through Shri J. C. Bhardwaj, The General Secretary H. P. AITUC Saproon-173211, District Solan (H. P.), and M/s. Birla Textile Mills Sai Road, Baddi, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिये भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Shri Mohinder Singh s/o Shri Jagmal Singh w.e.f. 24-8-1999 by M/s Birla Textile Mills, Baddi without any charge, enquiry and without complying section 25-F of the Industrial Dispute Act, 1947 on completion of 20 years of service, is legal and justified? If not, what relief of service benefits including continuity of service and amount of compensation the above workman is entitled to?"

"Whether the workman has abandoned the job at his own, as alleged by management? if so, its effect?"

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-2/93 (लेब 0) आई 0 डी 0 भाग/2002/Solan —अधो-हस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kailash Chand Gupta s/o Shri Dina Nath through Shri J. C. Bhardwaj, The General Secretary, H.P. AITUC Head Quarter, Saproon, District Solan (H. P.) and M/s Birla Textile Mills, Sai Road, Baddi, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिये भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"1. Whether the termination of the services of Shri Kailash Chand Gupta through Shri J. C. Bhardwaj, Gen. Secy. H. P. AITUC, Saproon, District Solan. w.e.f. 3-7-2000 by M/s Birla

Textile Mills Sai Road, Baddi on completion of more than 240 days continuous service and without giving any notice, chargesheet and without complying section 25-N of Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified?" If not, what relief of service benefits, the above workman is entitled to?

2. "Whether the workman has abandoned the job on his own, as alleged by the management If so, what its effect?"

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

सं 011-2/93 (लेब 0) आई 0 डी 0 भाग/2002/Solan.—अधो-हस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dilwara Singh s/o Shri Pritam Singh through Shri J. C. Bhardwaj, The General Secretary, H. P. AITUC Saproon, District Solan (H. P.) V/s The General Manager, M/s Contermann Pipers (I) Ltd., Bharatgarh Road, Nalagarh-174101, Himachal Pradesh के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Shri Dilwara Singh s/o Shri Pritam Singh w.e.f. 21-1-1999 by M/s Contermann Pipers (I) Ltd., Bharatgarh Road, Nalagarh, District Solan (H. P.) without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of section 25-N of Industrial Disputes Act, 1947 on completion of more than 240 days of continuous of service, as alleged is legal and justified? If not, what relief of service benefits including continuity in service and amount of compensation the aggrieved workman is entitled to?"

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-2/93 (लेब 0) आई 0 डी 0 भाग-सोलन.—अधो-हस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Krishan Mohan Chadha s/o Late Shri T. C. Chadha, House No. 487, Deonghat, Solan (H. P.) and the Managing Director, Himachal Tin Printers Pvt. Ltd., 300, Tagore Park Extension, Model Town 1st, Delhi-110009, 2. The Manager, M/s Himachal Tin Printers Pvt. Ltd., Deonghat, P. O. Saproon, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of service of Shri Krishan Mohan Chadha s/o Late Shri T. C. Chadha by the Managing Director, Himachal Tin Printers Pvt. Ltd., 300, Tagore Park Extension, Model Town 1st, Delhi-110009. 2. The Manager, M/s Himachal Tin Printers Pvt. Ltd., Deonghat, P. O. Saproon, District Solan, (H. P.) w.e.f. 24-2-2001, who was working as a Manager as alleged by the above management without complying the provisions of the Industrial Dispute Act, 1947 is proper and justified? If not what relief of service benefits and amount of compensation Shri Krishan Mohan Chadha is entitled to?"

"Whether Shri Krishan Mohan Chadha has abandoned the job at his own? If so, its effect?"

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-6/2001 (लेब 0) आई 0 डी 0 भाग-सिरमौर.—अधो-हस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Meena Ram s/o Shri Sairu, Village Jablog, P. O. Andhari, Tehsil Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh and the Divisional Forest Officer, Forest Division, Renukaji, District Sirmaur, Himachal Pradesh के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the plea of the Divisional Forest Officer, Renuka Forest Division, Renuka, District Sirmaur that Shri Meena Ram s/o Shri Sairu daily waged Beldar had left the job by his own accord w.e.f. year, 1993 is proper and justified? If not, what back wages, seniority service benefit and relief the concerned workman is entitled to?"

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-6/85 (लेब) आई 0 डी 0 भाग/2002/शिमला.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री कृपा राम सुपुत्र श्री भजनु, गांव मशराह, डा 0 धारचान्दना, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि 0 प्र 0) तथा मण्डलीय प्रबन्धक, हि 0 प्र 0 राज्य वन मण्डल, चौपाल, जिला शिमला (हि 0 प्र 0) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

“क्या श्री कृपा राम सुपुत्र श्री भजनु को मण्डलीय प्रबन्धक, हि० प्र० राज्य वन निगम, वन मण्डल चौपाल, जिला शिमला द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ, 25-एन की अनुपालना किए बिना दिनांक 31-12-1993 के पश्चात् नौकरी से छंटनी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है? अगर नहीं, तो श्री कृपा राम किस वरिष्ठता, सेवा लाभ एवं राहत का पात्र है?”

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-6/85 (लेब० आई० डी० भाग/2002/शिमला.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री हेत राम, गांव बोधना, डा० एवं तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०) तथा अधिशासी अभियन्ता, हि० प्र० राज्य विद्युत परिषद् मण्डल चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

“क्या श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री हेत राम भूतपूर्व दैनिक वेतन भोगी कामगार को अधिशासी अभियन्ता, हि० प्र० राज्य विद्युत परिषद् मण्डल चौपाल, जिला शिमला द्वारा दिनांक 1-3-1998 से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की अनुपालना किए बिना काम से निकाला जाना उचित और न्याय संगत है? अगर नहीं, तो कामगार श्री ज्ञान चन्द किस वरिष्ठता, सेवा लाभों व राहत का हकदार है?”

शिमला-1, 5 अगस्त, 2002

संख्या 11-6/85 (लेब० आई० डी० भाग-Shimla-2002 — अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Rai Singh s/o Sh. Relu Ram, Village Sangoli, P. O. Chanoli, Sub-Tehsil Kupvi, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.) and the Sub-Divisional Officer (S. D. O.) H. P. S. E. B. Sub-Division Khalini, Shimla (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1)

के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the termination of the services of Shri Rai Singh s/o Sh. Relu Ram, Ex-daily Wages Beldar by the Sub Divisional Officer, H. P. S. E. B. Sub Division Khalini, Shimla-171 002 w. e. f. November. 1994 without serving any notice is proper and justified? If not, what relief of service benefits, the above workman is entitled to?”

शिमला-1, 7 अगस्त, 2002

संख्या 11-2/93 (लेब० आई० डी० भाग-Brotiwala/2002.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Shyam Singh workman s/o Shri Mangat Ram, village Manakpur Thakurdas, P. O. Pinjore, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula, Haryana and M/s Pamwi Tissues Ltd., Barotiwal, Distt. Solan H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the services of workman Shri Shyam Singh have been reinstated by M/s Pamwi Tissues Ltd., Barotiwal, Distt. Solan. H P, in compliance to the Order of Labour Court, dated 7-12-1996 (Copy of award enclosed)? If not, its effects with relation to his wages and consequential service benefits and other advantageous payments from the period w. e. f. 8-12-1996 onwards to date which is to be adjudicated by the Labour Court?”

शिमला-1, 7 अगस्त, 2002

संख्या 11-2/93 (लेब० आई० डी० भाग/2002/Solan.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bala Ram s/o Shri Nek Ram, Village Adgu, P. O. Kuji, Tehsil Pachhad, District Sirmaur H. P. and 1. The Divisional Forest Officer, Rajgarh, District Sirmaur, H. P., 2. The Range Officer, Narang, Distt. Sirmaur H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि या तो श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1)

के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्री न्यायालय/प्रौद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

“Whether the termination of the services of Shri Bala Ram s/o Shri Nek Ram w. e. f. 13-12-2000

by the Divisional Forest Officer, Rajgarh without complying the provision of section 25-G, 25-H of Industrial Dispute Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief in service benefits including seniority and back wages the above workman is entitled to?”

हस्ताक्षरित/-
अमायुक्त

भाग-4—स्थानीय स्वायत्त शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग
शून्य

भाग-5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और बिज्ञापन

न्यायालय श्री अमरजीत सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती जीरो पत्नी श्री जर्मतो, निवासी डोलुआ, परगना जूठ,
उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर द्वारा 13 (3)

श्रीमती जीरो पत्नी जर्मतो, निवासी डोलुआ, परगना जूठ, उप-तहसील भलेई ने इस कार्यालय में एक दरखास्त दी है जिसमें लिखा है कि उसके पति के दो लड़के हैं, पहला लड़का गुलजार मुहमद व दूसरा रफीक है। गुलजार मुहमद का पंचायत परिवार रजिस्टर भाग-II में लड़का शब्द लिख कर आयु 40 वर्ष दर्ज है, जबकि उस लड़के की जन्म तिथि 7-4-89 की है। दूसरा लड़का नामक रफीक, जिसकी जन्म तिथि 3-8-91 की है परन्तु इसका नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

अब बजरिया इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त लड़कों की जन्म तिथियों की दस्तुती व पंचायत अभिलेख में दर्ज करने द्वारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस इशतहार के प्रकाशित होने उपरान्त अन्दर माह अपना एतराज इस न्यायालय में पेश कर सकता है। बाद मियाद उजर काबले समाप्त न होगा।

ग्राज दिनांक 25-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर।

अमरजीत सिंह,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री अमरजीत सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी चुराह,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती दिनेश कुमारी पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी मलीन्द्रो (लवोडी), परगना जूठ, तहसील सलूनी, जिला चम्बा।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर द्वारा 13 (3)

श्रीमती दिनेश कुमारी पत्नी मनोज कुमार, निवासी मलीन्द्रो (लवोडी), परगना जूठ, तहसील सलूनी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में एक दरखास्त पेश की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी लड़की नामक अंबली, जिसका जन्म दिनांक 31-5-2001 को हुआ था, जो ग्राम पंचायत ठाकरी मटी के परिवार रजिस्टर में मेरे पति के परिवार के साथ दर्ज है। अब दर्ज करने द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया है।

अब बजरिया इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त लड़की का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने द्वारा किसी का कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस इशतहार के जारी होने उपरान्त अन्दर-अन्दर माह इस न्यायालय में पेश कर सकता है। बाद मियाद उजर काबले समाप्त न होगा।

ग्राज दिनांक 25-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर।

अमरजीत सिंह,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री अमरजीत सिंह, मैरिज आफिसर-कम-उप-मण्डल
दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा

रतो देवी पुत्री राम दयाल, साकिन कुम्होड, परगना बगोड, तहसील चुराह, नरैण सिंह पुत्र देवी राम, साकिन पलनोटी, परगना तोसा, तहसील चुराह।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त बाबत शादी प्रमाण-पत्र लेने द्वारा।

रतो देवी व नरैण सिंह ने इस न्यायालय में दरखास्तें गुजारी हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने आपस में अन्तर्जातीय शादी कर ली है तथा अब न्यायालय से शादी प्रमाण-पत्र लेने द्वारा अनुरोध किया है।

बजरिया इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि शादी प्रमाण-पत्र जारी करने में किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस इशतहार के जारी होने उपरान्त अन्दर माह अपना एतराज इस न्यायालय में पेश कर सकता है। बाद मियाद उजर काबले समाप्त न होगा।

ग्राज दिनांक 25-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर।

अमरजीत सिंह,
मैरिज आफिसर-कम-उप-मण्डल, दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री अमरजीत सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह,
जिला चम्बा

श्री भोट पुत्र सनद, निवासी लोहदडी, परगना पिछला डिमूर, तहसील सलूनी, जिला चम्बा।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त बाबत जन्म तिथि दस्तुत करने द्वारा।

श्री भोट पुत्र समदू, निवासी लोहदही, परगना पिठला डिपूर, तहसील सलूनी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में एक दरखास्त गुजारी है जिस में उसने लिखा है कि उसकी दो पुत्रियां नामक शोना व परखीना हैं। परखीना की जन्म तिथि 20-1-1984 व शोना की जन्म तिथि 13-8-1986 है, जो सही व दस्त है, परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में शोना की जन्म तिथि 13-8-78 की जगह 13-8-86 व परखीना की जन्म तिथि 10-1-86 की जगह 20-1-84 दर्ज की जावे।

अब बजरिया इश्तहार ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि जन्म तिथियां दस्त करने में किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह एतराज इस इश्तहार के जारी होने के उपरान्त अन्दर माह पेश कर सकता है। बाद मियाद उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।
अमरजीत सिंह,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा।

न्यायालय श्री अमरजीत सिंह, मैरिज आफिसर-कम-उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अमर राम पुत्र श्री बेली राम, साकिन खखरी, परगना तीसा, तहसील चुराह, सोबतू पुत्री श्री नरेण सिंह, साकिन पतोगन, परगना तीसा, तहसील चुराह।

बनाम
ग्राम जनता

शादी प्रमाण-पत्र लेने बारा।

श्री अमर राम पुत्र श्री बेली राम व सोबतू पुत्री श्री नरेण सिंह, साकिन पतोगन ने इस न्यायालय में दरखास्त गुजारी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन दोनों ने अन्तर्जातीय विवाह कर लिया है तथा अब शादी प्रमाण-पत्र लेने बारा न्यायालय से अनुरोध किया है।

अब बजरिया इश्तहार द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त शादी प्रमाण-पत्र जारी करने में एतराज हो तो वह अपना एतराज इस इश्तहार के जारी होने उपरान्त अन्दर माह अपना उजर पेश कर सकता है। बाद मियाद उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।
अमरजीत सिंह,
मैरिज आफिसर-कम-उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विजय चन्दन, मैरिज आफिसर-कम-उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

1. श्री कुलदीप चन्द सुपुत्र श्री अंगत राम, गांव रियालड़ी, डाकघर जन्धारा, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. श्रीमती नीना रानी सुपुत्री श्री रूप लाल, गांव कैहड़, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ... प्रार्थीण।

बनाम
ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र खेर धारा 16 प्राफ स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत शादी पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री कुलदीप चन्द व श्रीमती नीना रानी प्रार्थीण ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक

30-4-2002 को गांव अंगू, तहसील व जिला हमीरपुर में हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार शादी की है जिसे स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जावे।

अतः ग्राम जनता तथा उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने वाले किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-9-2002 को समय सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी को पंजीकृत करने वाले आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।
विजय चन्दन,
मैरिज आफिसर-कम-उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री बोकल चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मन्शा देवी पत्नी श्री प्रभू राम, वासी भुक्कड़, मोजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम
ग्राम जनता

विषय.—दरखास्त बराए तस्वीक इन्तकाल नं0 848, टीका भुक्कड़, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश मकफूद-उन-खबरी।

श्रीमती मन्शा देवी पत्नी श्री प्रभू राम, निवासी टीका भुक्कड़ ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका पति श्री प्रभू राम पुत्र श्री सुर्जन, निवासी टीका भुक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 20-25 वर्षों से लापता है जिसके जीवित या मृत होने बारे कोई भता-पता न है। जिसकी बरास्त वारसान जेर इन्तकाल नं0 848, टीका भुक्कड़ दिनांक 31-5-2001 दर्ज रजिस्टर है।

अतः राजपत्र इश्तहार हिमाचल प्रदेश व टीका हजा भुक्कड़ में मुस्ती मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उसके पति प्रभू राम पुत्र सुर्जन, निवासी टीका भुक्कड़ की बरास्त इन्तकाल फैसला बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-8-2002 को अदालत में हाजर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अलबता हाजर न आने की सुरत में नियमानुसार इन्तकाल फैसला वारसान कर दिया जाएगा। बाद में कोई उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 25-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।
गोकल चन्द शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा:

कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, जिला कांगड़ा

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम जनता ।

श्री ओंकार सिंह ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है कि उसकी पौत्री शिवानी का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। उसकी पौत्री की जन्म तिथि 15-12-1997 है तथा बच्चे का जन्म पटका गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस का नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 29-8-02 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आकर पेश करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती आशना देवी पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी भलवाल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम जनता ।

श्रीमती आशना देवी ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र मनमोहन सिंह का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। उसके पुत्र की जन्म तिथि 8-11-1982 है तथा बच्चे का जन्म भलवाल गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस का नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 29-8-2002 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आकर पेश करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मांहर ।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

सुभाष चंद

बनाम

आम जनता ।।

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं तिथि मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री सुभाष चन्द ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके भान्जे शंखर का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। इसके भान्जे की जन्म तिथि 24-9-1996 तथा बच्चे का जन्म गांव हरमुहाल करोल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एक यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री करतार चन्द, पुत्र श्री जोहली राम, निवासी बरोटा जागीर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री करतार चन्द ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी पुत्री प्रियंका देवी का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। इसकी पुत्री की जन्म तिथि 14-10-1998 तथा बच्चे का जन्म गांव बरोटा जागीर, जो 0 पी 0 गगरही, तहसील देहरा जिला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस का नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती रचना कुमारी पत्नी श्री जगदीप सिंह, निवासी बरहून, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्रीमती रचना कुमारी ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र अरुण कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए उसके पुत्र की जन्म तिथि 26-3-1997 है तथा बच्चे का जन्म गांव बरहून तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने वाले कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

व मुकद्दमा :

श्री तरसेम धीमान पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी अप्पर धलौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम
आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री तरसेम धीमान ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी पुत्री तनिका का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 7-11-99 है तथा बच्चे का जन्म सोझर धलौर गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने वाले कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर हो कर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, (हि० प्र०)।

व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

व मुकद्दमा :

श्री मोहिन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुख देव शर्मा, गांव अर्जुन नागा, ज्वालामुखी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम
आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म तिथि एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969।

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री मोहिन्द्र कुमार ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र नैनाशी शर्मा का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 27-7-1998 है तथा बच्चे का जन्म गांव अर्जुन नागा, ज्वालामुखी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने वाले कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

व मुकद्दमा :

गुरचरन सिंह बनाम आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री गुरचरन सिंह ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र गुलशन कुमार पुत्र श्री गुरचरन सिंह का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 15-3-1997 है तथा बच्चे का जन्म बैरू गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने वाले कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर हो कर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

व मुकद्दमा :

श्री दिनेश कुमार सुपुत्र खजान सिंह, ज्वालामुखी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम
समस्त जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1966.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री दिनेश कुमार ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र सुमित कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज

नहीं करवाया गया है, अब दर्ज किया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 15-3-1997 है तथा बच्चे का जन्म ज्वालामुखी गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश कर करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा :

श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री धर्म पाल, निवासी गांव शेर लोहरा, डाकघर बनखंडी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

समस्त जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अशोक कुमार ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र साहिल कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है, अब दर्ज किया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 30-12-1996 है तथा बच्चे का जन्म गांव शेर लोहरा में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा :

श्रीमती चन्दना देवी बिधवा श्री अनिल कुमार, वासी गुटेड़, डाकघर डिंगर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती चन्दना देवी ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र विशाल कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है, अब दर्ज किया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 29-10-1999 है तथा बच्चे का जन्म गुटेड़ गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा :

श्री तरसेम धीमान पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी अण्णर, धनौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तरसेम धीमान ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी पुत्री प्रिया धीमान का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है, अब दर्ज किया जाए। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 14-4-1997 है तथा बच्चे का जन्म निचली धनौर गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा,
जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा :

श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी देहरा, डाकघर चनौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री मोहिन्दर सिंह ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी पुत्री राधू कुमारी का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है, अब दर्ज किया जावे । उसकी पुत्री की जन्म तिथि 1-5-1996 है तथा बच्चे का जन्म गांव बिहार, डाकखाना चनौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में हुआ है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समस्त अदालत में हाजिर आ कर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 17-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नेक राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

विक्रम सिंह बनाम ग्राम जनता ।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री दास राम, निवासी गांव बल्हा, डाकघर डल झील, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी पुत्र लक्ष्मी की जन्म तिथि 27-3-1997 है परन्तु ग्राम पंचायत करेरी में जन्म पंजीकृत न है । अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें ।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे लक्ष्मी का जन्म पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-9-2002 को असावन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 7-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।
नेक राम ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री सन्त राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

हरक बहादुर बनाम ग्राम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री हरक बहादुर मुपुत्र श्री कालू राम, निवासी जशरांगल, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी पुत्र की जन्म तिथि 26-9-1996 है परन्तु ग्राम पंचायत पक्षर में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है । अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें ।

इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 29-8-2002 को असावन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 10-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।
सन्त राम,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री सन्त राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

काली कुमार बनाम ग्राम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री काली कुमार मुपुत्र श्री नारंग राम, निवासी जवाहर नगर, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 11-11-1997 है परन्तु ग्राम पंचायत मन्त में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है । अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें ।

इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2002 को असावन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 10-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री सन्त राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

प्यारे लाल बनाम ग्राम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री प्यारे लाल मुपुत्र श्री भीम सैन, निवासी झिकनी बडोल, मौजा बयारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 3-8-2000 है परन्तु ग्राम पंचायत उपरली बडोल में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है । अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें ।

इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2002 को असावन या वकालतन हाजिर आकर उजर

पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने वाले आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 4-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सन्त राम,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सन्त राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बीना देवी

बनाम

ग्राम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी थाथरी, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्मा दायर किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 24-6-1996 है परन्तु ग्राम पंचायत सोकनी दोकोट में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे के जन्म पंजीकरण किए जाने वाले कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने वाले आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सन्त राम,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सन्त राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्मा संख्या : 20/02

सुनील कुमार

बनाम

ग्राम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री नीका राम, निवासी सकाह, मौजा सकाह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्मा दायर किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 15-12-1996 है परन्तु ग्राम पंचायत सकाह में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे के जन्म पंजीकरण किए जाने वाले कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने वाले आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने वाले आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सन्त राम,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सन्त राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्मा संख्या : 13/02

सोहन लाल

बनाम

ग्राम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्री सोहन लाल सुपुत्र श्री विशन दास, निवासी वणी, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्मा दायर किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 28-7-1996 है परन्तु ग्राम पंचायत योल में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे के जन्म पंजीकरण किए जाने वाले कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने वाले आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सन्त राम,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सन्त राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्मा संख्या : 34/02

मितरू राम

बनाम

ग्राम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्री मितरू राम सुपुत्र जैसी राम, निवासी बड़ोल, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्मा दायर किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 4-11-96 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत बड़ोल में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएंगे।

इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे के जन्म पंजीकरण किए जाने वाले कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने वाले आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सन्त राम,
नायक तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

आज दिनांक 5-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राम चन्द कौशल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, भू-सुधार अधिकारी एवम् तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत श्री जगदीश राम, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 10/दरुस्ती

तारीख पेशी : 2-9-2002

ब मुकद्दमा :

श्री छज्जू राम पुत्र हौन्स राम, साकन हाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

श्री दलीप सिंह सुपुत्र श्री मिलखी राम, वासी जण्डौर, तहसील जमवां कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादीगण।

ग्राम जनता

विषय.—दरखास्त दर्ज किये जाने वाले दरुस्त नाम हौन्स राम।

राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में हजरी राम दर्ज है परन्तु पंशन पास बुक बैंक व परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत अभिलेख में मेरे पिता का नाम हौन्स राम है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त हौन्स राम का नाम दरुस्त करने वाले अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 2-9-2002 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है वरना उसका नाम दरुस्त करने द्वारा निर्देश बहक सम्बन्धी राजस्व अभिलेख नियमानुसार कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुषमा वत्स,
भू-सुधार अधिकारी एवं तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

मोहर।

जगदीश राम,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री राम चन्द कौशल, कार्यकारी दण्डाधिकारी इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत श्री मनोहर लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री युवराज पठानियां पुत्र बजरंग सिंह, निवासी मकडोली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा।

श्री ज्ञान चन्द मुपुत्र श्री दलीप, निवासी चलवाहा, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री युवराज पठानियां ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती बीना पठानियां ने एक लड़के को दिनांक 31-1-1998 को गांव मकडोली में जन्म दिया है। जिसका नाम व जन्म तिथि रजिस्टर मकडोली में दर्ज न करवाया है।

अतः इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तिथि पंजीकरण वाले किसी को कोई एतराज हो तो वह निर्धारित दिनांक 31-8-2002 को वरवक्त 10.00 बजे असालतन व वकालतन अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के एतराज न होने की सूचना में श्री युवराज पठानियां के प्रार्थना-पत्र के आधार पर श्री अंकुश पठानियां के जन्म का पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

1. हरि चन्द पुत्र भीखा, 2. खुशी राम पुत्र सन्त राम, 3. मकन्द लाल, 4. दुनी चन्द, 5. रतन सिंह पुत्रान नन्द लाल, 6. मोहन लाल, 7. तिलक राज, 8. केवल सिंह पुत्रान गिरधारी लाल, 9. पिचू राम पुत्र राम दित्ता, 10. मान चन्द, 11. पूर्ण चन्द पुत्रान फरेगी, 12. जय देई पुत्री फरेगी, 13. विमला देवी पुत्री दलीपा, 14. देस राज पुत्र मंगत राम, 15. राकेश कुमार पुत्र धनू, 16. राधा देवी, 17. सुरजीत कौर, 18. सुभगा देवी, 19. चन्द्र कान्ता पुत्रियां, 20. विशाली देवी विधवा धनू, 21. जगत राम पुत्र नन्धू, 22. हरनाम सिंह, 23. अशोक कुमार पुत्रान जय सिंह, निवासीयान चलवाड़ा, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

दरखास्त बराये तकसीम आराजो खाता नं 352, खतौनी नं० 862, ता० 871, खसरा नं० 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1766, 1767, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1763, 1764, 1765, 1761, 1762, 2699/1735 2701/1736, 1777, 1778, 1779, 1780, कित्ता 23, रकबा ता० 0-93-79 हैउयेर मीटर, वाक्या मुहाल चलवाड़ा, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गये। परन्तु प्रतिवादीगण नौकरी पेक्षा या शादी-शुद्धा होने के कारण उन पर समनों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी। अतः बजरीया इशतहार उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 3-9-2002 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में असातन या वकालतन हाजिर आकर मुकदमा की पैरवी करें अन्यथा पैर-हाजरी की सूरत में उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोहर लाल,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० पी० शांडिल्य, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकदमा : तकसीम तारीख पेशी : 31-8-2002.

राजिन्द्र सिंह आदि बनाम धर्म सिंह आदि

प्रार्थना-पत्र तकसीम बावत भूमि खाता नं० 65, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 66, कुल खाता जारी 10, वाक्या मुहाल पैल, मौजा लोधवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

प्रतिवादी श्री टेक चन्द पुत्र श्री मनी राम, निवासी मुहाल लोधवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त दावा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादी श्री टेक चन्द पुत्र मनी राम, निवासी मुहाल लोधवां की हाजरी जरूरी है। प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा समन जारी किये गये लेकिन तामील समन नियमानुसार न हो सकी है। उक्त प्रतिवादी का स्थाई पता आसानी से उपलब्ध न हो रहा है, उसकी तामील साधारण ढंग से सम्भव न है इसलिए उपरोक्त प्रतिवादी को बजरीया इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा मुकदमा की पैरवी कर सकता है। निश्चित तिथि पर उपस्थित न होने की सूरत में उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० पी० शांडिल्य,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० पी० शांडिल्य, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकदमा : तकसीम

तारीख पेशी : 31-8-2002

राजिन्द्र सिंह बनाम धर्म सिंह आदि

प्रार्थना-पत्र तकसीम बावत भूमि खाता नं० 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 137, 138, 167, 179, 180, 181, कुल खाताजाना 27, वाक्या मुहाल टिपरी, मौजा लोधवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा।

नोटिस बनाम :

प्रतिवादी श्री टेक चन्द पुत्र मनी राम निवासी मुहाल लोधवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादी श्री टेक चन्द पुत्र श्री मनी राम, निवासी मुहाल लोधवां, मौजा लोधवां, तहसील नूरपुर की उपरोक्त मुकदमा में हाजरी जरूरी है। प्रतिवादी को न्यायालय से कई बार समन जारी किये गये लेकिन तामील समन नियमानुसार न हो सकी है। प्रतिवादी का स्थाई पता आसानी से उपलब्ध न हो रहा है उसकी तामील साधारण ढंग से सम्भव न है। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादी को बजरीया इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अदालत हजा में दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे असातन अथवा वकालतन उपस्थित होकर मुकदमा की पैरवी कर सकता है। निश्चित तिथि पर उपस्थित न होने की सूरत में उसके विरुद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० पी० शांडिल्य,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० पी० शांडिल्य, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकदमा : तकसीम

तारीख पेशी : 31-8-2002

देस राज बनाम खेमदी राम बगैरा

प्रार्थना-पत्र तकसीम बावत भूमि खाता नं० 64, खतोनी नं० 118, कित्ता 1, रकबा तादादी 0-35-01 हैक्टियर मीटर वाक्या मुहाल कूठन्दल, मौजा खेहर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, जमाबन्दी साल 1996-97.

नोटिस बनाम :

1. खेमदी राम पुत्र नरंगू, 2. मदन सिंह उपनाम ग्रोम प्रकाश पुत्र खेमदी राम, 3. राजेश कुमार पुत्र खेमदी राम, 4. शाम लाल पुत्र सुखा राम, सभी निवासीगण मुहाल कूठन्दल, मौजा खेहर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त दावा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादियों की हाजरी जरूरी है। उपरोक्त प्रतिवादियों को न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किये गये लेकिन तामील समन नियमानुसार न हो सकी है प्रतिवादियों का स्थाई पता आसानी से उपलब्ध न हो रहा है उनकी तामील साधारण ढंग से सम्भव न है इसलिए उपरोक्त प्रतिवादियों को बजरीया इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अदालत हजा में दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा मुकदमा की पैरवी कर सकते हैं। निश्चित तिथि पर उपस्थित न होने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० पी० शांडिल्य,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० पी० शांडिल्य, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्मा : तकसीम

तारीख पेशी : 31-8-2002

बलदेव सिंह, नरोत्तम सिंह पुत्रान श्री हरदित सिंह, निवासीगण
मुहाल वाण, मौजा भंडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल
प्रदेश

बनाम

विक्रमजीत सिंह पुत्र श्री जर्म सिंह व अन्य, निवासीगण
मुहाल वाण, मौजा भंडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

प्रार्थना-पत्र तकसीम बाबत भूमि छाता नं० 26, खतौनी
नं० 49, किते 7, रकबा तादादी 0-56-73 हेक्टेयर मीटर, वाक्या
मुहाल वाण, मौजा भंडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी साल 1995-96.

नोटिस बनाम :

1. विक्रमजीत सिंह, 2. अजय कुमार, 3. संजय कुमार पुत्रान जर्म सिंह,
4. वीर सिंह पुत्र जीतू, सभी निवासीगण मुहाल वाण, मौजा भंडवार,
तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त दावा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है
जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण की हाजरी बहरी है। उपरोक्त
प्रतिवादियों को न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किये गये
लेकिन तामील समन नियमानुसार न हो सकी है, प्रतिवादियों का
स्वार्थ पता आसानी से उपलब्ध न हो रहा है उनकी तामील
साधारण ढंग से न हो रही है। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादियों को
बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि वे
अदालत हुआ में दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं
अथवा अधिवक्ता द्वारा मुकद्मा की पैरवी कर सकते हैं। निश्चित
तिथि पर उपस्थित न होने की सूरत में उनके खिलाफ नियमा-
नुसार एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
से जारी हुआ।

मोहर।

आर० पी० शांडिल्य,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रक्कड़,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब मुकद्मा :

कमलेश कुमारी

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर द्वारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,
1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्रीमती कमलेश कुमारी ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि
उसकी पुत्री निवात्री का जन्म पंचायत रजिस्टर में गवती से दर्ज
न करवाया गया है, अब दर्ज किया जावे। उसकी पुत्री की जन्म
तिथि 12-7-99 तथा बच्चे का जन्म सरड बमी गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों
को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त का नाम

दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 31-8-2002
समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं या किसी वांछित के
माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा
एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील रक्कड़,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री वी० आर० कपिल, तहसीलदार एवं कार्यकारी
दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुघीर भवस्थी

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर द्वारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्मा उनवान वाला में श्री सुधीर भवस्थी पुत्र श्री ठाकुर
दास, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)
ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि मेरे लड़के श्रेय भवस्थी
पुत्र श्री सुधीर भवस्थी का जन्म दिनांक 23-1-1992 को हुआ
है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में
पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित
किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी को कोई
उजर व एतराज हो तो वह तिथि 2-9-2002 को असालतन
व बकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे आवें तथा अपने
उजर व एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में
लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

वी० आर० कपिल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वी० आर० कपिल, तहसीलदार एवं कार्यकारी
दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मंगत राम, निवासी रक्कड़, डा०
रहनु, तहसील शाहपुर।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर द्वारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्मा बारा में श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मंगत राम,
निवासी स्नेहड़, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना की
है कि मेरे पिता मंगत राम पुत्र श्री रूपा राम की मृत्यु तिथि
23-5-1983 को हुई थी लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत
रेहलू के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित
किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी को कोई

उजर या एतराज हो तो वह तिथि 2-9-2002 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत आवें तथा अपने उजर व एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्य-वाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० कपिल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० सी० नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश

दवा छेरिंग पुत्र नवांग तन्जिन, गांव छेलिंग कोठी वरवोग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दवा छेरिंग पुत्र नवांग तन्जिन, निवासी छेलिंग कोठी वरवोग ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की यंगचेन लामो का जन्म दिनांक 16-7-1999 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वरवोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 1-9-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित केलंग में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत्र में प्रार्थना-पत्र श्री दवा छेरिंग पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 2-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

बी० सी० नेगी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लाहौल स्थान केलंग (हि० प्र०)।

व अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी चच्योट, स्थित गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

व मुकद्दमा :

श्री हेमप्रभ पुत्र नरोत्तम, निवासी बटान्द, डाकघर मझार, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हेमप्रभ पुत्र नरोत्तम, निवासी बटान्द, डाकघर मझार, तहसील चच्योट, जिला मण्डी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की कुमारी भासा देवी की जन्म तिथि 24-4-2000 है तथा भूलवश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थरजुण में दर्ज नहीं हुई है। जिसे अब दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वजनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें उक्त जन्म तिथि दर्ज

करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 30-8-2002 से पूर्व हाजिर अदालत आकर पेश करें अन्यथा ग्राम पंचायत थरजुण को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चच्योट, स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब अदालत एस० एल० बंसल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

श्री टेक सिंह पुत्र पूर्ण चन्द, निवासी सदेहड़ा, डाकघर सिध-याणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—नाम दस्तुती बारे।

श्री टेक सिंह पुत्र पूर्ण चन्द, निवासी सदेहड़ा, डाकघर सिध-याणी ने इस अदालत में दख्खास्त गुजारी है कि उसका सही नाम टेक सिंह है जो कि ग्राम पंचायत अभिलेख सिधयाणी में गलती से टेक चन्द दर्ज हुआ है। जिसकी दस्तुती हेतु प्रार्थना करता है।

अतः बजरिया इशतहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त टेक सिंह के नाम दस्तुती बारा अगर किसी भी प्रकार का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-8-2002 को अपने उजर/एतराज असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर पेश कर सकता है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबिले समायत न होगा एवं उपरोक्त के नाम दस्तुती बारा आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस० एल० बंसल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री एन० एल० वर्धन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

संतोष कुमार पुत्र व कुमारी निर्मला पुत्री व कुन्ता विधवा अमर नाथ पुत्र जयकरण, निवासी कश्मूला, इलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी

फरीकदोयम।

बनाम

बृजलाल पुत्र व गीता, तुलसी, सवित्री, ज्ञानदेई हरदेई पुत्रियां व बोहरी विधवा जयकरण पुत्र भजन्, निवासी कश्मैला, इलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०) फरीकदोयम।

विषय :—प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता खतीनी नम्बर 22/22 रकबा तादादी-0-81-77 हैबटेयर वावया मुहाल कश्मैला है।

प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में भूमि खाता खतीनी नम्बर 22/22 रकबा तादादी 0-81-77 हैबटेयर वावया मुहाल व कश्मैला की तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु उन पर साधारण तरीके से तामील नहीं हो पा रही है। अब अदालत को पूर्ण विश्वास हो गया है कि फरीकदोयम को साधारण ढंग से समन की तामील नहीं हो सकती है। अतः फरीकदोयम को इस इशतहार द्वारा सूचित किया

जाता है कि वह दिनांक 2-9-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-7-02 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एन0 एल0 वर्धन,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एन0 एल0 वर्धन, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक:

संतोष कुमार पुत्र व निर्मला पुत्री व कुन्ता विधवा, अमर सिंह पुत्र जयकरण, निवासी कश्मिला, इलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश फरीकदोयम।

बनाम

वृज लाल पुत्र व श्रीमती गीता, तुलसी, सवित्री, जानदेई, हरदेई पुत्री व श्रीमती बोहरी देवी, विधवा जयकरण पुत्र भजन्, निवासी कश्मिला, इलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश फरीकदोयम।

विषय—प्रार्थना-पत्र तकसीम खाता खतीनी नम्बर 80/87 मुहाल दगडोन, इलाका हटली है।

प्रार्थीगण ने भूमि खाता खतीनी नम्बर 80/87 रकवा तादादी 0-07-12 हैक्टर वाक्य मुहाल दगडोन को तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु उन पर साधारण तरीके से तामील नहीं हो पा रही है। अब अदालत को पूर्ण विश्वास हो गया है कि फरीकदोयम को साधारण ढंग से समनों की तामील नहीं हो सकती है। अतः फरीकदोयम को इस इस्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 2-9-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एन0 एल0 वर्धन,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत पुष्पेन्द्र राजपूत, उपमण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0) शिमला,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुमित्रा देवी सुपुत्री स्व0 श्री मान सिंह

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुमित्रा देवी ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती मथरू देवी पत्नी मान सिंह को मृत्यु दिनांक 12-9-1986 को हुई है लेकिन उनकी ग्राम पंचायत नेरी के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है। अतः अब दर्ज की जाये।

अतः इस अदालती इस्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदिका की माता की मृत्यु ग्राम

पंचायत नेरी के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 3-9-2002 तक या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। पुष्पेन्द्र राजपूत (भा0 प्र0 से0)
उपमण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0),
शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत पुष्पेन्द्र राजपूत, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0) शिमला,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री अभी राम, गांव नेरी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री राकेश कुमार ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका अपना नाम राकेश कुमार आयु 28-5-1972, श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी आयु 16-8-1976, अखिल पुत्र आयु 11-9-1999, श्री अभी राम पिता 15-2-1946 श्रीमती चन्द्र कला माता 30-4-1949, श्रीमती सरजू देवी दादी 4-4-1926, राजेश कुमार भाई 31-3-1968, श्रीमती सरोजना देवी भाभी 8-10-1971, कु0 अशमिता भतीजी 16-7-1996, असीम भतीजा 21-5-1998, श्री गोपाल कृष्ण भाई 14-11-1978 उनकी ग्राम पंचायत नेरी के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखा है, अब दर्ज किया जाए।

अतः इस अदालती इस्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त आवेदक के परिवार को उनकी ग्राम पंचायत नेरी के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 2-9-2002 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ है।

मोहर। पुष्पेन्द्र राजपूत,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0),
शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री पुष्पेन्द्र राजपूत, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0) शिमला,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री पप्पू राम पुत्र श्री रलिया राम, गांव डोंटा, डाकघर वैह, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री पप्पू राम ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसने अपना नाम बदल कर पप्पू को जाह

संसार चन्द चलेल रहा है। जो ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रतः अब दर्ज किया जाए।

अतः इस भद्रालती इशतहार द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक का नाम बदलने/उनके विभाग के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 5-9-2002 तक या उससे पूर्व इस भद्रालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उनके विभाग सम्बन्धित को नाम अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

पुष्पेंद्र राजपूत,
उपमण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा०),
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

इशतहार जेर आर्डर 5 ब्लूज 20 जावता दिवानी

व भद्रालत श्री प्रताप सिंह रनौत, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुन्ती, जिला शिमला (हि० प्र०)

तस्दीक इन्तकाल नं० 4 मोजा वाटडू, प० छोटाबल, तहसील सुन्ती, जिला शिमला (हि० प्र०) मकफूद उलखवरी नीला दत्त पुत्र देवी सरन, निवासी घाटडू, प० छोटा बल, तहसील सुन्ती, जिला शिमला।

नोटिस ब्रानाम :

श्री नील दत्त पुत्र देवी सरन, निवासी मोजा वाटडू, तहसील सुन्ती, जिला शिमला (हि० प्र०)।

दोगने तस्दीक इन्तकाल नं० 4 मोजा वाटडू, प० छोटाबल, तहसील सुन्ती, जिला शिमला दर्ज होना पाया गया है। जिसमें श्री नील दत्त पुत्र देवी सरन, निवासी घाटडू, वर्ष 1980-81 से लापता है तथा उसे इस अवधि में कहीं देखा नहीं गया है। इस लिए अनुमान लगाया जाता है कि श्री नील दत्त जीवित नहीं है।

अतः बर्बरिया इशतहार श्री नील दत्त को सूचित किया जाता है कि यदि वह जीवित है तो वह अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मिति 2-9-2002 को प्रातः 10 बजे हाजिर असालतन व वकालतन आवे। अन्यथा इन्तकाल वहक देवी चन्द पुत्र व श्रीमती नोदावरी विधवा नील दत्त तस्दीक किया जावेगा।

आज दिनांक 27-7-2002 हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत जारी किया गया।

मोहर।

प्रताप सिंह रनौत,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्ती, जिला शिमला।

Himachal Pradesh Marketing Board, Vipnan Bhawan,
Khalaji, Shimla-2

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 13th August, 2002

No. HMB-(B) 2-18/97-3308.—In exercise of the powers conferred under section 3(10) and 18(2) of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Act, 1969 (Act No. 9 of 1970) and in pursuance of Rules 17 and 98 of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Rules, 1971 and all other powers conferred under the provisions of the said Rules, the Himachal Pradesh Marketing Board vide Resolution No. 7(a) of its meeting held on 15-5-2002 is hereby pleased to make the following amendments to the Recruitment and Promotion Rules for the post of Marketing Officer in the Himachal Pradesh Marketing Board :—

In Rule-11 the following :—

“By promotion from amongst the Assistant Secretary having 5 years regular service or regular

combined with *ad hoc* (rendered up to 31-3-1999) service in grade failing which having 10 years of service as Assistant Secretary and Market Supervisor combined, failing which both by deputation or contract. For Promotion training in Marketing is must.”

May be substituted as :—

“By promotion from amongst the Assistant Secretary having 5 years regular service or regular combined with *ad hoc* (rendered upto 31-3-2002) service in grade failing which having 10 years of service as Assistant Secretary and Market Supervisor combined, or from amongst Market Supervisors having 20 years of regular service failing which both by deputation or contract. For promotion training in Marketing is must.”

By order,

Sd/-

CHAIRMAN,

H. P. Marketing Board, Shimla-2.

In the Court of Shri Padam Singh, Sub Judge 1st Class,
Rampur Bushahr, District Shimla, H. P.

In re :—

Case No. 45-1 of 2001

Sh. Chiranji Lal Verma son of Sh. Sukh Nand Verma, r/o Village Bahali, P. O. Bhutti, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H. P.

Plaintiff.

Versus

National Insurance Company Ltd. through its Divisional Manager, Himdand Hotel Circular Road, Shimla, H. P. and others

Defendent.

Suit for Recovery of Rs. 55,124/-

Whereas in the above noted case, plaintiff has filed the case in this court for the suit of recovery of Rs. 1,55,124/- and the same is fixed for 2-9-2002 for the service of defendant.

Hence, this proclamation u/o 5, Rule 20, C. P. C. is hereby issued against the defendant Sh. Satvinder Singh Driver c/o Sh. Kishore Kumar s/o Sh. Amrit Lal, District Kinnaur, H. P. to appear before this Court on 2-9-2002 at 10.00 A.M. personally or through authorised agent or pleader to defend the case failing which the above noted defendant shall be proceeded against *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the court today this 20th day of July, 2002.

Seal.

PADAM SINGH,

Sub-Judge, 1st Class,

Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

व भद्रालत श्री डी० घार० वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर

मिसल नं० 8/95

दावा तकसीम

श्री रत्न नाम पुत्र श्री माडू राम, निवासी मोजा ओगनी, तहसील नाहन

प्रार्थी।

ब्रानाम

1. श्री अनिल कुमार, 2. श्री कमलेश कुमार, 3. श्री अरविन्द कुमार, 4. श्री अमित कुमार, 5. श्रीमती मनोजिता, 6. श्रीमती अमिता, 7. श्रीमती सुमित्रा, 8. श्रीमती जगन्नाथ पुत्रगण/पुत्रीयां/विधवा श्री कृष्ण चन्द, निवासीगण नाहन, तहसील नाहन, 9. श्री तेज

राम, 10. श्री मंगता राम पुत्र श्री जोता राम, निवासी मैनथपल, तहसील नाहन प्रत्यार्थीगण।

दावा तकसीम अराजी खाता/बतौनी नम्बर 72/85, नम्बर खसरा 162 तादादी रकबा 0-12 विस्था बाका मौजा, रामपुर जाटान, तहसील नाहन।

उपरोक्त प्रतिवादी नम्बर 1 ता 0 8 निवासीगण नाहन की तामील साधारण तौर पर को जानी असम्भव है। इस प्रकरण में तकसीम मौका हो चुकी है जिससे वादी व प्रतिवादी नं० 9, 10 सहमत है। अतः इस इशतहार के द्वारा प्रतिवादी नं० 1 ता 8 को सूचित किया जाता है कि अगर तकसीम अराजी बारे किसी भी किस्म का उजर व एतराज हो तो इस अदालत में असालतन या वकालतन मिति 29-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर करें वसूरत गैरहाजरी कार्यवाही एक तरफा अभल में लाई जाकर छन्द तकसीम तैयार करके मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 28-5-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर।
डि० आर० वर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र०।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दीप चन्द सुपुत्र दुवान चन्द, डाकखाना मानपुर देवड़ा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा (13)3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दीप चन्द सुपुत्र दुवान चन्द, डाकखाना मानपुर देवड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के/लड़की का जन्म दिनांक 19-4-1999, 18-5-2000 को हुआ परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मानपुर देवड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री दीप चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।
संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री के० एल० शुक्ला, गांव व डाकखाना पांवटा, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अनिल कुमार सुपुत्र के० एल० शुक्ला, गांव व डाकखाना पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की विनिता का जन्म दिनांक 11-11-1999 को हुआ परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री अनिल कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।
संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कान्ता पुत्री श्री दया राम, निवासी भदवाड़ी, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कान्ता पुत्री श्री दया राम, नि० भदवाड़ी तह० पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 17-12-1983 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिल्ला के रिकार्ड में 17-12-1994 दर्ज की गई है जो गलत है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-02 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती कान्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-02 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।
संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि० प्र०।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामपाल, नि० नारीवाली, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामपाल, नि० नारीवाली, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म

दिनांक 1-7-1984 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपना जन्म तिथि ग्राम पंचायत अजोली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-02 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री अशोक कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-02 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उपमण्डल दण्डाधिकारी पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री लक्ष्मण पुत्र उत्तम, निवासी गोंदपुर, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लक्ष्मण पुत्र उत्तम, निवासी गोंदपुर, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता शांति देवी की मृत्यु दिनांक 10-8-1989 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अमरकोट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री लक्ष्मण पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरजीत सिंह पुत्र बतन सिंह, निवासी गोंदपुर, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरजीत सिंह पुत्र बतन सिंह, निवासी गोंदपुर, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बच्चों का जन्म दिनांक 22-2-1989 व 14-6-1980 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत अमरकोट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री हरजीत सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रती राम पुत्र श्री नानकू, निवासी डांडा, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रती राम पुत्र श्री नानकू, निवासी डांडा, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के निखिल का जन्म दिनांक 2-2-2000 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत डांडा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री रती राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राज कुमार पुत्र श्री बेनी प्रसाद, निवासी ताख्वाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राज कुमार पुत्र श्री बेनी प्रसाद, निवासी ताख्वाला, पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके स्वयं का जन्म दिनांक 30-3-1966 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसका जन्म ग्राम पंचायत बट्टीपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक

28-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत्र में प्रार्थना-पत्र श्री राज कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29-7-2002 की मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जुग्गी पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी राजवन, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जुग्गी पुत्र नन्द लाल, निवासी राजवन पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के विरजू का जन्म दिनांक को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसका जन्म ग्राम पंचायत राजवन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत्र में प्रार्थना-पत्र श्री जुग्गी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री केदार सिंह, निवासी माणू, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बिमला देवी पत्नी केदार सिंह, निवासी माणू पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के/लड़की का जन्म दिनांक 12-3-1997, 10-3-1998 1-4-1999 एवं 2-2-2002 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनके जन्म ग्राम पंचायत जाभना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में

असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत्र में प्रार्थना-पत्र श्रीमती बिमला देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री मन्ना राम, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री मन्ना राम, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता राजो देवी की मृत्यु दिनांक 1-2-1998 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत निहालगढ़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत्र में प्रार्थना-पत्र श्री मोहिन्द्र सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री राम पाल पुत्र श्री माधु राम, निवासी सिंगपुरा, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम पाल पुत्र श्री माधु राम, निवासी सिंगपुरा, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की काजल का जन्म दिनांक 28-5-1998 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भगानी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई

आपत्ति प्राप्त न होने की सूचित में प्रार्थना-पत्र श्री राम पाल पर निप्रमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

आज दिनांक 26-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

मोहर।

संजय शर्मा,
उप-महडल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

व अदालत जनाब रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

व अदालत जनाब रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

दिलावर सिंह

वनाम

ग्राम जनता।

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

राज कुमार

वनाम

ग्राम जनता।

श्री राज कुमार पुत्र गोपाल दास, गांव नंगल जरियालां, डा0 नंगल जरियालां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी ढोलबह अरुणा रानी सुपुत्री श्री गुरदियाल सिंह, तहसील व जिला होगियारपुर के साथ दिनांक 19-5-2002 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जावे।

श्री दिलावर सिंह पुत्र श्री गुरदियाल सिंह, गांव व डा0 ओयल, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी गुरचरण कौर सुपुत्री श्री निरन्जन सिंह, गांव व डा0 ओयल, तहसील अम्ब, जिला ऊना के साथ दिनांक 2-4-2001 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबले समाप्त न होगा।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता ग्राम तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कोई शादी पंजीकरण बारे एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-8-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबले समाप्त न होगा।

आज दिनांक 24-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

—शून्य—

भाग—7 भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

—शून्य—

अनुपूर्वक

—शून्य—